नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 190, नई दिल्ली, गुरुवार 15 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र



● 03 धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

● 06 युवा शक्तिः शिक्षा, संस्कार और कौशल–सशक्त भविष्य के तीन स्तंभ

● 08 राज्यपाल बनाये जाने पर ब्रजमोहन राम ने 400 वर्ष पुरानी मंदिर मे मां उग्रतारा की पूजा की

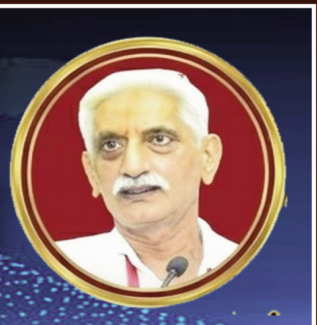
परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुंचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुंचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष
न्यूज दूरदर्शन

बड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गूंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

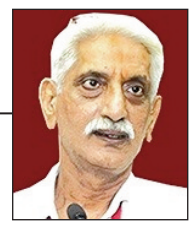
आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर मे "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।



संजय बाठला
मुख्य संपादक

₹10,000 के PUCC जुर्माने की समीक्षा की मांग - प्रदूषण नियंत्रण के साथ न्यायसंगत और अनुपातिक प्रवर्तन जरूरी

"साफ़ हवा और सही तरीके से लागू करना — साथ-साथ हो सकता है — और होना भी चाहिए।" - (Clean Air and Fair Enforcement Can — and Should — Go Together)



प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष

मीडिया हेतु — जनहित प्रतिनिधित्व: — पी. एस. बहल, भारतवर्ष के एक जागरूक और कानून का पालन करने वाले नागरिक

भूमिका: सवाल जुर्माने का नहीं, अनुपात का है दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वाहनों के प्रदूषण की जाँच और वैध PUC Certificate की अनिवार्यता का पूरा समर्थन करते हुए, एक जनहित प्रतिनिधित्व के माध्यम से ₹10,000 के No PUCC जुर्माने की समीक्षा, पुनर्विचार और अनुपातिकता पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि ₹10,000 की penalty वर्तमान कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है और इसे उच्च स्तर पर policy decision के रूप में लागू किया गया है, जनहित में इसकी समीक्षा या पुनर्विचार की मांग करना फिर भी आवश्यक है, विशेषकर तब जब अन्य Motor Vehicle Act violations के मुकाबले PUCC से संबंधित चूक पर इतनी बड़ी समान राशि निर्धारित की गई है।

प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक PUC lapse के लिए ₹10,000 का समान दंड हर परिस्थिति में वास्तव में proportionate और न्यायसंगत है?

मुख्य तथ्य: कानूनी और संवैधानिक ढांचा

तथ्य 1: Motor Vehicles Act, 1988 (संशोधित 2019)

– धारा 190(2): निर्धारित प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर ₹10,000 जुर्माना का प्रावधान

– Central Motor Vehicles Rules, 1989 — नियम 115, 116: PUC प्रमाणपत्र, Emission Test, वाहन निरीक्षण की व्यवस्था

– राजपत्रित अधिसूचना: 2019 संशोधन के बाद जुर्माना राशि बढ़ाई गई

तथ्य 2: संविधान के मौलिक अधिकार

– अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता — समान परिस्थितियों में समान, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार का सिद्धांत

– अनुच्छेद 19(1)(g): व्यापार और आजीविका का अधिकार — अत्यधिक दंड से आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए

– अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार — सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार से जोड़ा है (M.C. Mehta vs Union of India, Subhash Kumar vs State of Bihar)

- अनुच्छेद 32 और 226: संवैधानिक उपचार — न्यायालय में समीक्षा की मांग का अधिकार

तथ्य 3: न्यायिक सिद्धांत — Proportionality Doctrine

सर्वोच्च न्यायालय ने Modern Dental College (2016), Anuradha Bhasin (2020), K.S. Puttaswamy (2017) में कहा है — राज्य की कोई भी कार्रवाई, भले ही जनहित में हो, अनुपातिक (Proportionate), तर्कसंगत और कम से कम हस्तक्षेपकारी होनी चाहिए। दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए।

तथ्य 4: PUCC क्या है? Pollution Under Control Certificate एक प्रमाणपत्र है जो यह दर्शाता है कि वाहन ने Emission Test पास किया है। यह प्रदूषण का प्रमाण नहीं, बल्कि प्रमाणपत्र की वैधता का प्रमाण है। प्रमाणपत्र न होना और वाहन द्वारा वास्तव में अधिक प्रदूषण करना — दो अलग बातें हैं।



बिन्दु 2: क्या कंप्यूटर-आधारित स्वतः चालान विधिसम्मत प्रक्रिया है? जनहित प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि बिना मौके पर जांच, बिना Emission Test, केवल डेटाबेस में तारीख समाप्त होने पर चालान काटना प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत — Audi Alteram Partem (सुनवाई का अधिकार) के विरुद्ध जा सकता है।

कानून में धारा 116 CMVR के तहत वाहन का मौके पर निरीक्षण और Emission Test का प्रावधान है। यदि जांच ही नहीं हुई, तो उल्लंघन कैसे सिद्ध हुआ? यह प्रश्न न्यायालयीन समीक्षा के योग्य है।

यह नहीं कहा जा रहा कि कानून अवैध है। मांग है कि प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित हो — पहले जांच, फिर प्रमाण, फिर दंड।

बिन्दु 3: पहली चूक बनाम Habitual Defaulter — अंतर जरूरी पहली या आकस्मिक PUC चूक और habitual/repeat defaulters के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

- पहली बार / 1-2 दिन की देरी: चेतावनी, छोटा जुर्माना, समय सीमा में PUC कराने का अवसर

- बार-बार नियम तोड़ने वाले, जानबूझकर बचने वाले: कड़ा जुर्माना, वाहन जब्ती तक कार्रवाई

– फर्जी PUC: आपराधिक कार्रवाई

Enforcement data के आधार पर यह भी देखा जाना चाहिए कि वास्तविक रूप से बार-बार नियम तोड़ने वाले और प्रमुख defaulters कौन हैं, ताकि enforcement की प्राथमिकता उन्हीं पर केंद्रित हो।

बिन्दु 4: पुराने दोपहिया वाहन और Proportionality की समस्या अत्यंत कम मूल्य के किसी पुराने दोपहिया वाहन पर ₹10,000 का जुर्माना उसके वाहन के वास्तविक मूल्य के बराबर या उससे भी अधिक हो सकता है, जबकि उस समय उसका actual emission भी स्थापित न हुआ हो।

ऐसे मामलों में proportionality और practical hardship को नीति-निर्माताओं एवं implementing authorities द्वारा गंभीरता से देखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 14 और 21 के अनुपातिकता सिद्धांत से सीधे जुड़ा है।

बिन्दु 5: केवल PUC Centres पर निर्भरता अपर्याप्त है विशेष रूप से, केवल PUC Centres की Testing पर निर्भरता पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। Pollution Enforcement Staff द्वारा अपने अधिकृत उपकरणों के साथ नियमित एवं Surprise Roadside Emission Testing को फिर से प्रभावी किया जाए, ताकि वास्तविक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों की मौके पर पहचान और कार्रवाई हो सके।

इससे प्रदूषण नियंत्रण का असली उद्देश्य पूरा होगा — कागज नहीं, हवा साफ होगी।

बिन्दु 6: दिल्ली-NCR का प्रदूषण केवल वाहनों से नहीं दिल्ली-NCR का प्रदूषण केवल वाहनों से नहीं होता। वाहन प्रदूषण के साथ-साथ धूल, उद्योग, निर्माण, बायोमास/कचरा जलाना, द्वितीयक प्रदूषण तथा क्षेत्रीय स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों पर समान रूप से वैज्ञानिक और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

इसलिए केवल वाहन मालिकों पर भारी आर्थिक दंड के माध्यम से pollution control का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। न्यायालय के कई आदेशों (GRAP, CAQM) में भी स्रोत-वार (Source Apportionment) कार्रवाई पर जोर दिया गया है।

बिन्दु 7: क्या मांग है और क्या नहीं है? जनहित प्रतिनिधित्व में यह स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य PUC व्यवस्था को कमजोर करना या प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राहत देना बिल्कुल नहीं है। बल्कि मांग यह है कि वास्तविक रूप से अधिक प्रदूषण करने वाले वाहनों, बार-बार नियम तोड़ने वालों, जानबूझकर नियमों से बचने वालों तथा फर्जी PUC के मामलों में और अधिक प्रभावी एवं कड़ी कार्रवाई हो।

मूल संदेश सरल है:

> PUC नियमों का पालन भी जरूरी है और प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई भी। लेकिन penalty ऐसी हो जो violation की प्रकृति, actual pollution, व्यक्ति की compliance history और वास्तविक public harm के अनुरूप हो।

निष्कर्ष: संविधान, न्याय और जनहित का संतुलन ₹10,000 की penalty की समीक्षा या कमी की मांग, pollution control के विरुद्ध नहीं है। यह केवल इस बात की मांग है कि कानून और enforcement व्यवस्था अधिक proportionate, practical, evidence-based और जनहितकारी बने।

संविधान हमें स्वच्छ वायु का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही न्यायसंगत प्रक्रिया और अनुपातिक दंड का अधिकार भी देता है। दोनों एक-दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं।

परिवहन विशेष का मत है — सरकार और विभाग को इस जनहित मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। समीक्षा करना लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं।

"Clean Air and Fair Enforcement Can — and Should — Go Together."

"साफ़ हवा और सही तरीके से लागू करना — साथ-साथ हो सकता है — और होना भी चाहिए।" — पी. एस. बहल, भारतवर्ष के एक जागरूक और कानून का पालन करने वाले नागरिक

— P.S. Bahl, A Concerned & Law-Abiding Citizen of Bharatvarsh

शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं पांचवीं देवी मां स्कंदमाता की आराधना

माँ की अनुपम ममता और आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे — मातृत्व, शक्ति और संतान कल्याण की अधिष्ठात्री देवी

प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष, अक्टूबर 2026



ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड | परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक | टेंपल ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत) | ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन (पंजीकृत) के प्रमुख साझा प्रबंधन मंडल की ओर से आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।

> "माँ की अनुपम ममता और कृपा सब पर बनी रहे यही कामना है हमारी।"

मुख्य तथ्य: मां स्कंदमाता का परिचय
नाम: स्कंदमाता — स्कंद (कार्तिकेय) की माता
नवरात्रि का दिन: पांचवां दिन
वाहन: सिंह
आसन: कमल पुष्प
स्वरूप: चार भुजाएं — गोद में बाल स्कंद, एक हाथ में कमल, एक हाथ में वरद मुद्रा
प्रिय पुष्प: पीला कमल, गुलाब
प्रिय भोग: केला
मंत्र: ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः

बिन्दु 1: मां स्कंदमाता की कथा भगवान कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है। जब देवासुर संग्राम में देवताओं को तारकासुर से पराजित होना पड़ा, तो देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद को देवसेनापति बनाया। स्कंद ने तारकासुर का वध किया और देवताओं की रक्षा की।

इसीलिए माता पार्वती का यह रूप स्कंदमाता कहलाया। माँ ने अपने पुत्र को गोद में लेकर भी युद्ध का नेतृत्व किया — यही मातृत्व और शक्ति का अद्भुत संगम है।

कहा जाता है कि मां स्कंदमाता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

बिन्दु २: आराधना और पूजा विधि

1. स्नान और संकल्प: प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। माता के समक्ष संकल्प लें।

२. कलश स्थापना: नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित कलश के समक्ष पीले फूल, अक्षत, रोली अर्पित करें।

३. दीपक और धूप: घी का दीपक जलाएं, गंगाजल से अभिषेक करें।

4. भोग: मां को केला, पीले फूल और मिष्ठान्न अर्पित करें। कहा जाता है मां को केला अति प्रिय है।

5. मंत्र जाप:

> ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः

> या देवी सर्वभू तेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

6. आरती: संध्या काल में मां की आरती करें और कन्याओं को प्रसाद वितरित करें।

बिन्दु ३: मां स्कंदमाता की महिमा — क्या फल मिलता है?

- संतान कल्याण: मां की पूजा से संतान की सभी बाधाएं दूर होती हैं, संतान को बुद्धि, साहस और स्वास्थ्य मिलता है।

- मातृत्व का आशीर्वाद: जो माताएं संतान के लिए चिंतित हैं, उन्हें मां स्कंदमाता की कृपा से विशेष शांति मिलती है।

- भय नाश: मां की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा, भय और ग्रह दोष समाप्त होते हैं।

- विद्या और विवेक: मां अपने भक्तों को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं।

- परिवार में सुख-शांति: मां की कृपा से घर में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि आती है।

बिन्दु 4: पांचवीं देवी का संदेश — ममता ही शक्ति है मां स्कंदमाता हमें सिखाती हैं कि ममता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। एक मां जब अपने बच्चे को गोद में लेकर युद्ध करती है, तो वह हार नहीं मानती।

आज की माताओं को भी इस संदेश की जरूरत है — अपनी संतान को संस्कार, साहस और करुणा तीनों देना। यही सच्ची नवरात्रि आराधना है।

निष्कर्ष: जनता के लिए कामना परिवहन विशेष की ओर से हम सबकी यही कामना है —

> माँ की अनुपम ममता और आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान कल्याण बना रहे।

शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार:

CSEAM सामग्री के त्वरित हटाने हेतु MeitY की प्रस्तावित सख्त प्रोटोकॉल योजना



पिंकी कुंडू

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से बाल यौन शोषण और दुरुपयोग सामग्री (CSEAM) की त्वरित रिपोर्टिंग और हटाने के लिए एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है। यह SOP नवंबर 2025 में अधिसूचित NCII (Non Consensual Intimate Imagery) प्रोटोकॉल पर आधारित होगी, जिसमें 24 घंटे के भीतर हटाने और बहु एजेंसी समन्वय का प्रावधान है।

यह कदम निम्न चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है: - सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर CSEAM का प्रसार। इ उपयोगकर्ताओं और अभिभावकों को ऐसी सामग्री की रिपोर्टिंग में कठिनाई। इ आईटी नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों द्वारा समान अनुपालन की आवश्यकता।

प्रस्तावित CSEAM SOP की प्रमुख विशेषताएँ

A. NCCRP पर समर्पित रिपोर्टिंग श्रेणी इ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) पर CSEAM रिपोर्टिंग के लिए अलग श्रेणी जोड़ी जाएगी। इ इससे तेज़ छंटाई, पीड़ित केंद्रित प्रक्रिया और विशेष साइबर इकाइयों को सीधा रूटिंग संभव होगा।

B. 24 घंटे की अनिवार्य हटाने की समयसीमा इ मध्यस्थों को शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की गई CSEAM सामग्री हटानी या निष्क्रिय करनी होगी। इ यह NCII SOP की समयसीमा के अनुरूप है।

C. बहु चैनल रिपोर्टिंग तंत्र रिपोर्टिंग के लिए निम्न माध्यम उपलब्ध होंगे: इ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के इन ऐप रिपोर्टिंग टूल। इ आईटी नियम, 2021 के तहत नियुक्त शिकायत अधिकारी। इ NCCRP (ऑनलाइन या हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से)। इ कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ (LEAs) जिनमें स्थानीय पुलिस स्टेशन शामिल हैं।

D. हैश मिलान और स्वचालित पहचान इ प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों को निम्न तकनीकें लागू करनी होंगी: o हैश मिलान तकनीकें o क्रॉलर सिस्टम ताकि पहले से चिन्हित CSEAM का पुनः अपलोड रोका जा सके।

E. अंतर एजेंसी समन्वय इस प्रोटोकॉल में शामिल होंगे: - भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) – CSEAM शिकायतों का केंद्रीय संकलक। - दूरसंचार विभाग (DoT) – ISP के माध्यम से URL ब्लॉकिंग। इ MeitY – अनुपालन की निगरानी और धारा 69A के तहत हटाने के आदेश जारी करना।

F. पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण इ SOP नाबालिगों और शिकायतकर्ताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। इ वन स्टॉप सेंटर (OSC) परिवारों को रिपोर्टिंग, परामर्श और कानूनी सहायता में मदद कर सकते हैं।

कानूनी एवं नियामक आधार

A. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इ धारा 67B CSEAM के प्रकाशन, प्रसारण या ब्राउज़िंग को अपराध घोषित करती है। इ धारा 69A MeitY को सार्वजनिक व्यवस्था और बाल सुरक्षा के हित में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

B. आईटी नियम, 2021 इ नियम 3(2)(b) मध्यस्थों को शिकायत प्राप्त होने पर बाल सुरक्षा का उल्लंघन करने वाली सामग्री हटाने का निर्देश देता है।- मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने और अनुपालन रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे।

C. NCII SOP के अनुरूपता इ NCII SOP (2025) संरचनात्मक टेम्पलेट प्रदान करता है: o 24 घंटे में हटाना o बहु एजेंसी समन्वय o हैश बैंक निर्माण o पीड़ित केंद्रित रिपोर्टिंग

संचालन कार्यप्रवाह (CSEAM SOP की संभावित संरचना)

चरण 1: उपयोगकर्ता/LEA रिपोर्टिंग इ शिकायत NCCRP, हेल्पलाइन 1930, इन ऐप रिपोर्टिंग या पुलिस स्टेशन के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

चरण 2: त्वरित रूटिंग इ NCCRP शिकायत को I4C और संबंधित प्लेटफ़ॉर्म के शिकायत अधिकारी को भेजेगा।

चरण 3: सत्यापन और छंटाई इ प्लेटफ़ॉर्म स्वचालित और मैनुअल दोनों तरीकों से त्वरित मूल्यांकन करेगा।

चरण 4: 24 घंटे के भीतर हटाना - सामग्री हटाई या निष्क्रिय की जाएगी; आवश्यकता पड़ने पर URL ब्लॉक किया जाएगा।

चरण 5: हैशिंग और रोकथाम-सामग्री को सुरक्षित CSEAM हैश बैंक में जोड़ा जाएगा ताकि पुनः अपलोड रोका जा सके।

चरण 6: रिपोर्टिंग बैक इ मध्यस्थ MeitY और I4C को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चरण 7: जांच और अभियोजन - LEAs डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू करेंगे, अपलोडर का पता लगाएंगे और धारा 67B के तहत कार्रवाई करेंगे।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) पर अपेक्षित प्रभाव

A. साक्ष्य संरक्षण में तेजी इ त्वरित हटाने से वायरल प्रसार कम होगा और मूल साक्ष्य सुरक्षित रहेंगे।

B. रिपोर्टिंग और वर्गीकरण में सुधार - NCCRP की समर्पित श्रेणी से LEAs को संरचित शिकायतें मिलेंगी, जिससे समय की बचत होगी।

C. बेहतर ट्रेसबिलिटी - मध्यस्थों के अनिवार्य सहयोग से IP लॉग, अकाउंट मेटाडेटा और डिवाइस फिंगरप्रिंट तक पहुँच आसान होगी।

D. पीड़ित को कम नुकसान इ त्वरित हटाने से पुनः प्रसार रोका जा सकेगा, जिससे नाबालिगों और परिवारों का आघात कम होगा।

E. अंतर एजेंसी समन्वय में वृद्धि - I4C, DoT, MeitY और राज्य साइबर सेल एकीकृत कार्यप्रवाह में काम करेंगे, जिससे दोहराव और विलंब कम होगा।

F. मजबूत निवारक नियंत्रण इ हैश मिलान और स्वचालित पहचान से पुनरावृत्ति अपराधों में कमी आएगी और LEA का कार्यभार घटेगा।

भारत की साइबर सुरक्षा रूपरेखा में रणनीतिक महत्व

* भारत को समर्पित CSEAM हटाने प्रोटोकॉल वाले देशों की श्रेणी में स्थापित करता है। इ भारत में कार्यरत वैश्विक प्लेटफ़ॉर्मों के लिए अनुपालन दायित्वों को सुदृढ़ करता है। इ अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों (INHOPE, INTERPOL) के अनुरूपता बढ़ाता है। इ भविष्य की श्रेणियों (जैसे डीपफेक बाल शोषण, सिंथेटिक CSAM) के लिए स्केलेबल मॉडल तैयार करता है।

MeitY का आगामी CSEAM हटाने SOP भारत की डिजिटल सुरक्षा संरचना में एक प्रमुख नीति सुधार है।

यहः- उपयोगकर्ताओं को सरल रिपोर्टिंग मार्ग प्रदान करेगा, - प्लेटफ़ॉर्मों पर सख्त अनुपालन समयसीमा लागू करेगा, इ LEA की क्षमताओं को सशक्त करेगा, और इ ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री के प्रसार को उल्लेखनीय रूप से कम करेगा।

यह प्रोटोकॉल भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति का मुख्य स्तंभ बनने की संभावना रखता है — NCII SOP के समान, परंतु अधिक सख्त प्रवर्तन और बाल केंद्रित सुरक्षा उपायों के साथ।

स्वच्छ हवा का सवाल: पराली, धूल और कचरे से मुक्ति कब?

डॉ. विजय गर्ग

स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ हवा अत्यंत आवश्यक है, लेकिन आज वायु प्रदूषण भारत के सामने पर्यावरण की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन गया है। हर वर्ष, विशेषकर सर्दियों के महीनों में, अनेक शहरों और कस्बों की वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। पराली जलाने की समस्या पर अक्सर लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन यह एक बड़ी समस्या का केवल एक हिस्सा है। सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, कचरा जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआँ और औद्योगिक प्रदूषण भी हवा को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यदि हम वास्तव में स्वच्छ हवा चाहते हैं, तो हमें किसी एक कारण तक सीमित रहने के बजाय उन सभी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं।

पराली जलाना: एक मौसमी चुनौती

पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में पराली जलाना हर वर्ष एक बड़ी मौसमी चुनौती बन जाता है। धान की कटाई के बाद कुछ किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेतों को जल्दी तैयार करने के उद्देश्य से फसल के अवशेषों को जला देते हैं। इससे धुआँ, सूक्ष्म कण और अन्य हानिकारक प्रदूषक वातावरण में फैल जाते हैं।

हालाँकि, किसानों को फसलों के बीच कम समय मिलने, मशीनों की अधिक लागत और बड़ी मात्रा में पराली के प्रबंधन जैसी व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केवल किसानों को दोष देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्हें सस्ती मशीनें, समय पर तकनीकी सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन और फसल अवशेषों के उपयोग के लिए विश्वसनीय बाजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

फसल अवशेषों से जैविक खाद, जैव ऊर्जा, बायोगैस और औद्योगिक उपयोग की सामग्री तैयार की जा सकती है। ऐसे विकल्पों को प्रोत्साहित करने से प्रदूषण कम होने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों से प्रदूषण

धूल भी वायु गुणवत्ता खराब होने का एक प्रमुख कारण है, विशेषकर तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में। कच्ची सड़कें, टूटी सड़कें, खुले में रखी निर्माण सामग्री, इमारतों को तोड़ने के कार्य और निर्माण स्थलों का खराब प्रबंधन हवा में धूल फैलाते हैं। धूल भरी सड़कों पर चलने वाले वाहन इन कणों को दोबारा हवा में उड़ा देते हैं। ये कण साँस के माध्यम से लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

निर्माण कार्यों के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए सामग्री को ढकना, आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव करना, निर्माण स्थलों को उचित रूप से घेरना और मलबे को ढके हुए वाहनों में ले जाना आवश्यक है। सड़कों के किनारों को पक्का और साफ रखा जाना चाहिए। मशीनों द्वारा नियमित सफाई करने से भी जमा हुई धूल कम की जा सकती है।

नगर निकायों और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण संबंधी नियमों का नियमित और प्रभावी ढंग से पालन हो।

कचरा जलाना: प्रदूषण का रोका जा सकने वाला स्रोत

घरेलू कचरे, प्लास्टिक, पत्तों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को खुले स्थानों पर जलाना खतरनाक और अनावश्यक है। कचरा जलने से धुआँ, सूक्ष्म कण और संभावित रूप से विषैले रसायन हवा में फैलते हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक और मिश्रित कचरे को जलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

इस समस्या के प्रमुख कारणों में कचरा संग्रहण की अपर्याप्त व्यवस्था, कचरे को अलग-अलग करने की आदत का अभाव और उचित निपटान सुविधाओं की कमी शामिल हैं। जब कचरा उठाने की व्यवस्था नियमित नहीं होती या मोहल्लों में उचित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो लोग कभी-कभी कचरे को जला देते हैं।

प्रत्येक घर में गीले कचरे, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री और शेष कचरे को अलग-अलग रखना चाहिए। गीले कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है, जबकि कागज, धातु, काँच और उपयुक्त प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए भेजा जा सकता है।

नगर निकायों को घर-घर से कचरा एकत्र करने, खुले में कचरा फेंकने पर रोक लगाने और कचरा जलाने की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए।

जन-जागरूकता के साथ-साथ आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी जरूरी है। यदि उचित व्यवस्था ही नहीं होगी, तो लोगों के लिए कचरे का जिम्मेदारी से प्रबंधन करना कठिन हो जाएगा।

वाहन और उद्योग भी जिम्मेदार हैं

वायु प्रदूषण केवल खेतों, सड़कों और कचरे से ही नहीं होता। कारों, मोटरसाइकिलों, ट्रकों और बसों से निकलने वाला धुआँ भी सूक्ष्म कणों और हानिकारक गैसों का स्रोत है। औद्योगिक उत्सर्जन और डीजल जनरेटर भी स्थानीय वायु गुणवत्ता को खराब कर सकते हैं।

बेहतर सार्वजनिक परिवहन, वाहनों की नियमित जाँच और रखरखाव, स्वच्छ ईंधन तथा प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों को अपनाकर इन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना चाहिए। अधिकारियों को प्रदूषण की निगरानी करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

जहाँ सुरक्षित और व्यावहारिक हो, वहाँ पैदल चलने, साइकिल चलाने और साझा परिवहन को प्रोत्साहित करके निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकती है।

क्या किया जाना चाहिए?

स्वच्छ हवा के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, किसानों, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

सबसे पहले, वायु गुणवत्ता की निगरानी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाधान तैयार किए जाने चाहिए।

दूसरा, पर्यावरण संबंधी नियमों को निष्पक्षता और निरंतरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब उल्लंघन की पहचान हो और उसे रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

तीसरा, किसानों को पराली जलाए बिना उसके प्रबंधन के लिए सहायता दी जानी चाहिए। आर्थिक सहायता, साझा मशीनरी केंद्र और कृषि अवशेषों के उपयोग के लिए लाभकारी बाजार टिकाऊ विकल्पों को अपनाना आसान बना सकते हैं।

चौथा, शहरी स्थानीय निकायों को सड़कों के रखरखाव, निर्माण स्थलों की धूल पर नियंत्रण तथा कचरा संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण और निपटान की प्रभावी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।

अंत में, स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और मीडिया को लोगों में यह समझ विकसित करनी चाहिए कि स्वच्छ हवा सभी की साझा जिम्मेदारी है। पर्यावरण शिक्षा केवल नारों और विशेष दिवसों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लोगों को व्यवहार में पर्यावरण के अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।



स्वच्छ हवा अधिकार है, विलासिता नहीं

वायु प्रदूषण सभी को प्रभावित करता है, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन या हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोग इसके प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। प्रदूषित हवा अस्थमा और साँस से जुड़ी अन्य समस्याओं को बढ़ा सकती है तथा हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकती है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य के साथ-साथ कार्यक्षमता, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण पर भी पड़ता है।

हमें वायु प्रदूषण को केवल सर्दियों की अस्थायी समस्या मानना बंद करना होगा। यह वर्ष भर बनी रहने वाली चुनौती है, जिसके समाधान के लिए निरंतर योजना, वैज्ञानिक निगरानी और जनभागीदारी आवश्यक है।

अब सवाल यह नहीं है कि पराली जलाना, धूल या कचरा प्रदूषण में योगदान देता है या नहीं। वास्तविक सवाल यह है कि क्या हम इन सभी स्रोतों से समान गंभीरता के साथ निपटने के लिए तैयार हैं?

स्वच्छ हवा केवल कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियानों, अस्थायी प्रतिबंधों या एक-दूसरे पर दोष लगाने से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यावहारिक समाधान, जिम्मेदार व्यवहार और निरंतर सहयोग की आवश्यकता है।

जिस दिन हमारे खेतों में फसल अवशेषों का टिकाऊ प्रबंधन होगा, सड़कों पर अनावश्यक धूल नहीं उड़ेगी, कचरे का उचित निपटान होगा और वाहन तथा उद्योग पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगे, उस दिन हम स्वस्थ वातावरण की दिशा में वास्तविक प्रगति कर सकेंगे।

स्वच्छ हवा केवल पर्यावरण का लक्ष्य नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की बुनियादी आवश्यकता है। कदम उठाने का समय अभी है, क्योंकि हर साँस अनमोल है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षिक स्तंभकार।
प्रख्यात वैज्ञानिक
गली कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट,
पंजाब – 152107

आम आदमी की थाली पर महंगाई का सर्जिकल स्ट्राइक 2026! महंगी थाली, जेब खाली और जनता परेशान!

खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत ने बढ़ाई सरकार की धड़कनें; सरकार की अग्निपरीक्षा! क्या 2027 के चुनावों में जनता वोट से देगी जवाब?

— लेखक: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र
— प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष

भूमिका: जब महंगाई रसोई की चौखट पार कर जाए जब महंगाई केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित रहती है, तब उसका प्रभाव बाजार की रिपोर्टों और सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देता है, लेकिन जब वही महंगाई रसोई की चौखट पार करके आम आदमी की थाली, परिवार के मासिक बजट, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और भविष्य की बचत पर चोट करने लगती है, तब वह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बन जाती है।

भारत में 14 अक्टूबर को सामने आए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर के 11.39 प्रतिशत तक पहुंचने के दावे, और 13 अक्टूबर को जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पहुंचने ने इसी गंभीर परिस्थिति की ओर संकेत किया है। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक मूल विज्ञप्तियों से होती है, तो यह स्थिति सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), उद्योग जगत और करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय होगी।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रसोई का खर्च लगातार बढ़ने लगे, तो आम परिवार अपनी जरूरतों, इच्छाओं और बचत के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाए?

मुख्य तथ्य: आंकड़े क्या कहते हैं? सूचकांक अगस्त 2026 सितंबर 2026 स्रोत
खुदरा महंगाई (CPI) 4.83% *5.54%* NSO विज्ञप्ति (दावा: 12/13 अक्टूबर)
थोक महंगाई (WPI) 9.92% *11.39%* DPIIT विज्ञप्ति (दावा: 14 अक्टूबर)
ईंधन एवं बिजली समूह (WPI) 22.93% *25.85%* थोक महंगाई आंकड़े
प्राथमिक वस्तुएं — *8.67%* WPI
विनिर्मित उत्पाद — *9.76%* WPI
थोक खाद्य सूचकांक 7.05% *8.66%* WPI

नोट: ये आंकड़े लेखक के प्रस्तुत विवरण के अनुसार हैं। पाठकों से अनुरोध है कि आधिकारिक NSO / DPIIT विज्ञप्ति से सत्यापन करें।

मुख्य बिन्दु 1: रसोई के बजट पर महंगाई का सीधा हमला भारतीय परिवारों के लिए रसोई केवल भोजन तैयार करने की जगह नहीं, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दाल, चावल, आटा, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, नींबू और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का असर लगभग हर आय वर्ग पर पड़ता है।

विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खाद्य पदार्थों की महंगाई अधिक कष्टकारी होती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है।

प्याज की कीमतों में असामान्य वृद्धि, लहसुन और अदरक के महंगे होते भाव तथा नींबू जैसी सामान्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को असंतुलित कर सकती हैं। शक्कर का खुदरा मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम बताए जाने का दावा भी उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ाता है, हालांकि वास्तविक बाजार भाव शहर, गुणवत्ता और बिक्री केंद्र के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।

महंगाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि परिवारों को समान आय में पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। कोई परिवार फल खरीदना कम करता है, कोई दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मात्रा घटाता है, तो कोई मनोरंजन, कपड़े और अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करता है। इस प्रकार महंगाई केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है।

मुख्य बिन्दु 2: खुदरा महंगाई 5.54%, थोक महंगाई 11.39% — खतरे की घंटी? खुदरा महंगाई बताती है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पिछले



वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितनी बदली हैं। दूसरी ओर, थोक महंगाई उत्पादकों और थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का संकेत देती है।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि 11.39 प्रतिशत थोक महंगाई का अर्थ यह नहीं है कि बाजार की प्रत्येक वस्तु 11.39 प्रतिशत महंगी हो गई है। इसका अर्थ है कि थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं के समग्र मूल्य स्तर में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इतनी वृद्धि दर्ज हुई है।

फिर भी, थोक महंगाई का लगातार ऊंचा रहना चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इससे कंपनियों की उत्पादन लागत, परिवहन खर्च और व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव पड़ सकता है। यदि कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, तो आने वाले महीनों में खुदरा बाजार में भी महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

मुख्य बिन्दु 3: ईंधन और कच्चे तेल का झटका — महंगाई की आग में घी सितंबर के थोक महंगाई आंकड़ों में सबसे चिंताजनक पहलू ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी है। ईंधन एवं बिजली समूह की महंगाई अगस्त के 22.93 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 25.85 प्रतिशत पहुंच गई।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई महंगी होने से सब्जियों, अनाज और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की लागत बढ़ सकती है। उद्योगों में बिजली, रसायन, प्लास्टिक, पैकेजिंग और दूसरे कच्चे माल का खर्च भी बढ़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा की महंगाई अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में एक साथ लागत का दबाव पैदा कर सकती है।

मुख्य बिन्दु 4: RBI की अग्निपरीक्षा — ब्याज दरें बढ़ेंगी या विकास प्रभावित होगा? बढ़ती महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नीतिगत चुनौती खड़ी करती है। सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत तक पहुंचने से यह दर RBI के 2 से 6 प्रतिशत के निर्धारित सहनशीलता दायरे की ऊपरी सीमा के अपेक्षाकृत करीब आ गई है।

ब्याज दरें बढ़ाने से कर्ज महंगा हो सकता है और मांग पर दबाव पड़ सकता है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। गृह ऋण, वाहन ऋण और व्यावसायिक कर्ज की लागत बढ़ने से परिवारों और कारोबारियों का खर्च बढ़ सकता है।

इसलिए केवल रेपो दर में बदलाव से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति या मौसम के कारण पैदा हुई महंगाई का समाधान नहीं किया जा सकता। इसके लिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ आपूर्ति प्रबंधन, बाजार निगरानी और समय पर सरकारी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता है।

मुख्य बिन्दु 5: महंगाई पर कानूनों की कसौटी — जमाखोरी पर कानून फिर भी हाहाकार!

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: जमाखोरी, कालाबाजारी और अत्यधिक मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण का मुख्य कानून। सरकार आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सीमा निर्धारित कर सकती है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: बाजार में एकाधिकार, कार्टेल और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा।

बड़ा सवाल: कानून हैं, फिर भी महंगाई से हाहाकार क्यों? कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, जमाखोरों पर समय पर कार्रवाई और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता की कमी ही आम उपभोक्ता को राहत न मिलने का कारण बन रही है।

मुख्य बिन्दु 6: ग्रामीण परिवारों की चिंता और घटता आर्थिक भरोसा महंगाई का सबसे गहरा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनकी आय सीमित है और जिनके पास अचानक बढ़े खर्चों से निपटने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है।

यदि परिवारों को लगता है कि आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों, परिवहन और घरेलू जरूरतों की कीमतें और बढ़ेंगी, तो वे गैर-जरूरी खरीदारी टाल सकते हैं और बचत को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसका प्रभाव ग्रामीण बाजार में दोपहिया वाहनों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य उत्पादों की मांग पर पड़ सकता है।

इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वह महंगाई के आंकड़ों के साथ आम परिवारों की क्रय शक्ति और वास्तविक जीवन-स्तर पर भी ध्यान दे।

मुख्य बिन्दु 7: 2027 के विधानसभा चुनाव — क्या महंगाई बनेगी बड़ा राजनीतिक मुद्दा? वर्ष 2027 में सात राज्यों — उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश — में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

यदि चुनाव से पहले खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरेलू जरूरतों की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो महंगाई विपक्ष के लिए प्रमुख मुद्दा और सत्तारूढ़ दलों के लिए कठिन परीक्षा बन सकती है।

मतदाता अपने दैनिक अनुभवों के आधार पर सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं। रोजगार, आय, कानून-व्यवस्था और विकास के साथ रसोई का बजट भी उनके निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

लेकिन यह मान लेना उचित नहीं होगा कि महंगाई अपने आप किसी निश्चित चुनावी परिणाम को जन्म देगी। मतदाताओं का फैसला अनेक मुद्दों, स्थानीय परिस्थितियों, नेतृत्व, सरकारी योजनाओं और राजनीतिक विकल्पों के सम्मिलित प्रभाव से बनता है।

निष्कर्ष: आंकड़ों से आगे बढ़कर रसोई को राहत देना जरूरी सितंबर 2026 के महंगाई आंकड़े सरकार और आर्थिक नीति निर्माताओं के सामने एक महत्वपूर्ण चेतावनी प्रस्तुत करते हैं। खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि कीमतों का दबाव व्यापक हो रहा है।

ऐसे समय में सरकार को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई करने, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं दूर करने और कमजोर आय वाले परिवारों को राहत देने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, RBI को महंगाई के रुझान, भविष्य के जोखिम और आर्थिक विकास के बीच संतुलित नीति अपनानी होगी।

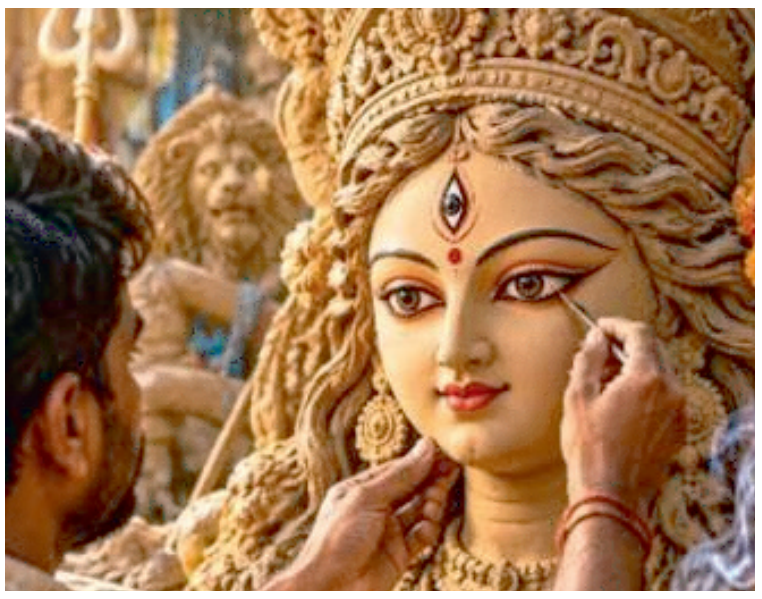
सरकार की आर्थिक सफलता का वास्तविक पैमाना केवल विकास दर या शेयर बाजार की चमक नहीं, बल्कि आम नागरिक की थाली में पौष्टिक भोजन, महीने के अंत में बची हुई बचत और भविष्य के प्रति उसका विश्वास भी है।

यदि महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता है, तो उसका असर बाजार से लेकर जनमानस तक दिखाई दे सकता है। और लोकतंत्र में जनता की आर्थिक चिंताएं अंततः चुनावी बहस का हिस्सा बनती हैं। इसलिए समय रहते महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और आम आदमी को वास्तविक राहत देना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा किसने बनाई थी ?



Ms. Aanchal Agarwal
working as PRT in one of the renowned school of Delhi Done PGDM in IT & HR, M.Com, B.Ed



क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, उससे जुड़ी एक अद्भुत कथा हजारों वर्षों से सुनाई जाती है? आखिर सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा किसने बनाई थी? इस रहस्य का संबंध राजा सुरथ और समाधि नाम के एक व्यापारी से है, जिनकी कथा देवी महात्म्य में वर्णित है।

प्राचीन काल में राजा सुरथ नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से प्रेम करते थे और कुशलता से अपने राज्य का संचालन करते थे। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि उनके शत्रुओं की शक्ति बढ़ने लगी। एक भयंकर युद्ध में राजा सुरथ को पराजय का सामना करना पड़ा। उनकी सेना कमजोर पड़ गई और उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा दुख तब हुआ, जब उनके अपने ही मंत्री और अधिकारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। जिन लोगों पर राजा ने भरोसा किया था, वही अब उनके अधिकार और सत्ता पर कब्जा जमाने में लगे थे।

राजा सुरथ का मन दुख और चिंता से भर गया। वे अपना राज्य खो चुके थे, लेकिन उनके मन से राज्य और प्रजा की चिंता दूर नहीं हो रही थी। वे सोचते रहते कि उनके घोड़े कैसे होंगे, उनकी सेना किस स्थिति में होगी और उनके राज्य का संचालन कौन कर रहा होगा। आखिरकार वे राजमहल से दूर वन की ओर निकल पड़े। भटकते-भटकते वे महर्षि मेधा के शांत आश्रम में पहुंचे। आश्रम का वातावरण देखकर उनके मन को कुछ शांति मिली। वहां ऋषि-मुनि तपस्या करते थे और प्रकृति के बीच शांत जीवन व्यतीत करते थे।

उसी आश्रम के आसपास राजा सुरथ की भेंट समाधि नाम के एक व्यापारी से हुई। समाधि कभी बहुत धनी व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन उनके अपने परिवार ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था। उनकी पत्नी और पुत्र उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें घर से अलग कर दिया, फिर भी व्यापारी का मन बार-बार अपने परिवार की ओर खिंचता था। वे जानते थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पत्नी और पुत्रों के प्रति उनका मोह समाप्त नहीं हो रहा था।

राजा सुरथ और व्यापारी समाधि दोनों की पीड़ा अलग-अलग थी, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न था। राजा को धोखा देने वाले मंत्री अब भी उनकी चिंता का कारण बने हुए थे और व्यापारी को दुख देने वाले परिवार के प्रति भी उनका मोह बना हुआ था। आखिर मनुष्य उन लोगों के बारे में ही क्यों सोचता रहता है, जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया हो? जब दोनों इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महर्षि मेधा के पास पहुंचे, तो ऋषि ने उन्हें संसार की एक गहरी सच्चाई समझाई।

महर्षि मेधा ने कहा कि यह संसार महामाया की शक्ति से संचालित होता है। यही शक्ति जीवों के मन में मोह उत्पन्न करती है। मनुष्य बहुत कुछ जानते हुए भी अपने प्रियजनों, संपत्ति, पद और संसार की वस्तुओं से बंधा रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी-कभी मोह के कारण सही और गलत का अंतर समझने के बाद भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। महामाया की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वही संसार को चलाती है और वही जीव को मोह से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाती है।

यह सुनकर राजा सुरथ और समाधि के मन में देवी के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने महर्षि से पूछा कि वे इस मोह से मुक्ति पाने और जीवन के सत्य को समझने के लिए क्या करें। महर्षि मेधा ने उन्हें आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना करने का मार्ग बताया। उन्होंने समझाया कि सच्चे मन से देवी की उपासना करने पर मनुष्य को ज्ञान, शांति और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की शक्ति प्राप्त हो सकती है।

महर्षि के मार्गदर्शन के बाद राजा सुरथ और समाधि वन में एकांत स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने नदी के किनारे मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा को उन्होंने केवल मिट्टी की आकृति नहीं माना, बल्कि उसमें आदिशक्ति के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। दोनों ने फूलों, पत्तों और उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से देवी की पूजा आरंभ की। वे अपना समय देवी के ध्यान, प्रार्थना और तपस्या में बिताने लगे। देवी महात्म्य की परंपरा के अनुसार, उन्होंने लंबे समय तक कठिन साधना की और देवी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की।

कथा में वर्णित है कि राजा सुरथ और समाधि ने अपनी तपस्या के दौरान अत्यंत कठोर नियमों का पालन किया। देवी के प्रति समर्पण व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर से रक्त की आहुति तक अर्पित की। यह प्रसंग उनकी अटूट श्रद्धा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए, लेकिन दोनों ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। उनके मन में अब केवल राज्य वापस पाने या धन-संपत्ति हासिल करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि वे देवी की कृपा और जीवन के गहरे सत्य को समझना चाहते थे।

आखिरकार उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए। देवी का दिव्य स्वरूप देखकर राजा सुरथ और समाधि भावविभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक मां को प्रणाम किया। देवी ने दोनों से उनकी इच्छाएं पूछीं। राजा सुरथ ने अपना राज्य वापस पाने और भविष्य में भी धर्मपूर्वक शासन करने का वरदान मांगा। दूसरी ओर, व्यापारी समाधि ने संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।

मां दुर्गा ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी की कृपा से राजा सुरथ को अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त हुआ और वे फिर से न्यायपूर्वक शासन करने लगे। समाधि को वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी तलाश में वे आश्रम आए थे। इस प्रकार एक ही देवी की आराधना से राजा को संसार में अपने कर्तव्य का मार्ग मिला और व्यापारी को मोह से मुक्ति पाने का ज्ञान प्राप्त हुआ।

इस कथा में राजा सुरथ के भविष्य से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। देवी ने उन्हें भविष्य में सावर्णि मनु के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। हिंदू परंपरा में मन्वंतर सृष्टि के एक विशाल कालखंड को कहा जाता है और सावर्णि मनु को आठवें मन्वंतर का मनु माना गया है। इस प्रकार देवी की कृपा केवल राजा के वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी कथा को भविष्य के एक बड़े ब्रह्मांडीय कालचक्र से भी जोड़ा गया।

राजा सुरथ और समाधि की यह कथा देवी महात्म्य में मां दुर्गा की महिमा, महामाया की शक्ति और सच्ची उपासना के महत्व को दर्शाती है। मिट्टी से देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का प्रसंग इसी कथा में मिलता है, इसलिए इसे देवी की प्रतिमा-पूजा की एक प्राचीन धार्मिक परंपरा से जोड़ा जाता है। हालांकि, आज की दुर्गा पूजा की सभी रीति-रिवाजों और सार्वजनिक पंडालों की शुरुआत इसी एक घटना से हुई थी, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में दुर्गा पूजा की अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई हैं।

मां दुर्गा की कृपा केवल धन, सत्ता या विजय प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। कोई भक्त संसार में अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति मांगता है, तो कोई मोह से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। मां अपने भक्तों की भावना के अनुसार उन्हें मार्ग दिखाती हैं। राजा सुरथ की कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए और समाधि की कथा बताती है कि सच्ची शांति बाहरी संपत्ति से नहीं, बल्कि मन के ज्ञान और विवेक से प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धापूर्वक मां दुर्गा का स्मरण करता है, वह उनसे साहस, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांग सकता है।

जय माता दुर्गा जी।



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

15 अक्टूबर 2026 | दिन का अंक: 8 — महत्वाकांक्षा, अधिकार, अनुशासन, धन और भौतिक प्रगति

मूलांक 1
धन व करियर: दिन का अंक 8 महत्वाकांक्षा, अधिकार और भौतिक विषयों को मजबूत करता है। किसी महत्वपूर्ण आर्थिक या पेशेवर विषय की जिम्मेदारी लें, लेकिन निर्णय अहंकार के बजाय तथ्य और लंबी अवधि के मूल्य पर आधारित रखें।
रिश्ते: आपकी मजबूत इच्छाशक्ति आज और तीव्र हो सकती है। सामने वाले की राय का सम्मान करें और साधारण मतभेद को अधिकार की लड़ाई न बनाएं।
सावधानी: अहंकार में खर्च, प्रभुत्व और स्वयं को साबित करने के लिए जोखिमपूर्ण निर्णय से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: काम में निर्णायक नेतृत्व करें और रिश्तों में बराबरी का सम्मान रखें।

मूलांक 2
धन व करियर: दिन 8 आपको धन, सीमाओं और अपने पेशेवर मूल्य के विषय में अधिक दृढ़ बनने को कहता है। जिम्मेदारियां और आर्थिक अपेक्षाएं स्पष्ट हों तो साझेदारी लाभ दे सकती है।
रिश्ते: आसपास का मजबूत रवैया आपको दबाव जैसा लग सकता है। चुप होने या जरूरत से ज्यादा समायोजन करने के बजाय अपनी बात शांत और स्पष्ट रखें।
सावधानी: आर्थिक निर्भरता, आत्म-संदेह और अधिकारपूर्ण व्यवहार को व्यक्तिगत लेने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: अपने मूल्य और सीमाओं के लिए नरमी के साथ दृढ़ रहें।

मूलांक 3
धन व करियर: आपकी संवाद क्षमता आज महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित कर सकती है। विचार आत्मविश्वास से रखें, लेकिन उनके साथ आंकड़े, संरचना और व्यावहारिक व्यावसायिक योजना भी दें।
रिश्ते: आकर्षण मदद करेगा, लेकिन गंभीर विषयों में सच्चाई जरूरी है। जिम्मेदारी से बचने के लिए मजाक या चतुर शब्दों का उपयोग न करें।
सावधानी: दिखावे के खर्च, अधिक वादा और सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक रचनात्मक विचार को मापने योग्य और व्यावहारिक अवसर में बदलें।

मूलांक 4
धन व करियर: दिन 8 आपकी अनुशासित प्रकृति के अनुकूल है और बजट, सिस्टम, संपत्ति, लंबी अवधि की योजना या जिम्मेदारी में मदद कर सकता है। प्रगति धीमी लेकिन मजबूत हो सकती है।
रिश्ते: कर्तव्य और व्यावहारिकता मजबूत रहेंगे, लेकिन रिश्तों में गर्मजोशी भी जरूरी है। हर बातचीत को नियम, काम या जिम्मेदारी तक सीमित न करें।
सावधानी: कठोरता, निराशावाद और धन के मामलों में अत्यधिक नियंत्रण से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक लंबी अवधि की योजना मजबूत करें और अपनापन दिखाने के लिए समय निकालें।

मूलांक 5
धन व करियर: दिन 8 आपकी गति और नेटवर्किंग क्षमता को व्यावसायिक परिणाम में बदल सकता है, यदि आप केंद्रित रहें। आत्मविश्वास से बातचीत करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक शर्तें ध्यान से पढ़ें।
रिश्ते: आप बंधन पसंद नहीं करेंगे, जबकि दूसरे प्रतिबद्धता चाह सकते हैं। अस्पष्ट संकेत देने के बजाय अपने इरादे स्पष्ट रखें।
सावधानी: सट्टा, शॉर्टकट और तुरंत लाभ के लिए प्रतिबद्धता बदलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: लचीलेपन का उपयोग जिम्मेदारी से बचने के बजाय गंभीर अवसर को बेहतर करने में करें।

मूलांक 6
धन व करियर: दिन 8 आर्थिक जिम्मेदारी, मूल्य और भौतिक सुरक्षा पर ध्यान देता है। मूल्य निर्धारण, पारिवारिक खर्च या व्यावसायिक व्यवस्था की समीक्षा करें, लेकिन भावनाओं को बजट नियंत्रित न करने दें।
रिश्ते: आप सभी के आराम की जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं। अपनों का साथ दें, लेकिन धन, उपहार या त्याग को ईमानदार संवाद का विकल्प न बनाएं।
सावधानी: परिवार पर जरूरत से ज्यादा खर्च, अधिकार भावना और दूसरों की जिम्मेदारी उठाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: समझदारी की योजना और स्पष्ट अपनापन से सुरक्षा बनाएं।

मूलांक 7
धन व करियर: दिन 8 आपकी गहरी सोच को व्यावहारिक परिणाम की ओर धकेलता है। निवेश, कॉन्ट्रैक्ट या करियर विकल्पों का पूरा शोध करें और प्रमाण मजबूत होने पर ही प्रतिबद्ध हों।
रिश्ते: दबाव बढ़ने पर आप पीछे हट सकते हैं। जो सोच रहे हैं उसे थोड़ा साझा करें ताकि आपकी चुप्पी को उदासीनता न समझा जाए।
सावधानी: संदेह, आर्थिक गोपनीयता और इतना विश्लेषण कि समय पर कदम ही न उठे—इनसे बचें।
दिन बेहतर बनाएं: गहरी सोच से एक ठोस निर्णय लें और उसे स्पष्ट रूप से बताएं।

मूलांक 8
धन व करियर: आपके मूलांक 8 और दिन के अंक 8 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। महत्वाकांक्षा, अधिकार, अनुशासन और धन पर फोकस बढ़ेगा। गंभीर काम के लिए शक्तिशाली दिन है, लेकिन अत्यधिक जोखिम या नियंत्रण से बचें।
रिश्ते: तीव्र ऊर्जा शक्ति संघर्ष पैदा कर सकती है। साथी या परिवार के साथ सम्मान, न्याय और भावनात्मक परिपक्वता जरूरी है।
सावधानी: प्रभुत्व, कठोर निर्णय, बदले की भावना में खर्च और केवल काम में डूबने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करें और सफलता को नियंत्रण नहीं, स्थिरता से मापें।

मूलांक 9
धन व करियर: दिन 8 आपकी उदार प्रकृति में आर्थिक अनुशासन लाता है। जिम्मेदारियां पूरी करें, लंबित भुगतान वसूलें और दूसरों की मदद स्पष्ट सीमा के भीतर ही करें।
रिश्ते: आप किसी और की समस्या हल करना चाह सकते हैं। करुणा दें, लेकिन लोगों को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेने दें।
सावधानी: अपराधबोध में देना, जल्दबाजी में उधार देना और पुरानी नाराजगी ढोने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक आर्थिक या भावनात्मक दायित्व को न्याय और परिपक्वता से पूरा करें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

आस्था ही जब बने जीवन रक्षा का महासंकल्प :

नवरात्रि विशेष: माँ दुर्गा के नौ रूप और हमारा सड़क सुरक्षा कवच



जल्दबाज़ी में ना खोएँ होश, सड़क सुरक्षा में ही है समझदारी का जोश। मिश्रा

हरिओम बाजपेई । नादान

सहायक परिवहन अधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने बड़े सरल शब्दों में नवरात्रि के आस्था के प्रतीक बने सुरक्षा कब्जो को जब स्वयं और दूसरो के जीवन की रक्षा का महासंकल्प लेकर नवरात्रि पूजन का अनुष्ठान करें तो नवरात्रि केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना, संयम और सुरक्षा का महापर्व वन जायेगा । इस पावन अवसर पर प्रदेश के हर घर में नवदुर्गा की पूजा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। माँ दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप, उनकी सवारी और उनके अस्त्र-शस्त्र हमें नकारात्मक प्रवृत्तियों पर विजय की प्रेरणा देते हैं। वर्तमान समय में सड़कों पर फैली अनुशासन हीनता, गति का अनियंत्रित सम्मोहन और लापरवाही किसी महिषासुर से कम नहीं है जो हर साल लाखों हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ देते हैं। यदि हम माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूपों, देवी कवच और पौराणिक कथाओं को सड़क सुरक्षा के व्यावहारिक नियमों से जोड़कर देखें, तो हमारी गृह-पूजा सड़कों पर जीवन बचाने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है ।भगवान विश्वकर्मा का अभेद्य कवच सुरक्षा उपकरणों का महत्वदुर्गा सप्त शती के द्वितीय अध्याय में वर्णन आता है कि जब महिषासुर के वध के लिए सभी देवताओं के तेज से देवी प्रकट हुईं, तब देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने माँ दुर्गा को अभेद्य कवच और अस्त्र प्रदान किए ताकि वे युद्ध भूमि में पूर्णतः सुरक्षित रहें ।आज के तकनीकी युग में जब हम वाहन लेकर



सड़क रूपी समर में उतरते हैं, तो हमारा विज्ञान और शिल्पकला द्वारा निर्मित आई एस आई मार्क हेलमेट, कार की सीट बेल्ट और एयरबैग ही वह सुरक्षा कवच हैं। दुपहिया चलाते समय हेलमेट पहनना और कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना माँ के उसी दिव्य कवच को धारण करने जैसा है, जो दुर्घटना के समय जीवन की रक्षा करता है। वही ऋषि मार्कण्डेय और ब्रह्मा जी के संवाद में देवी कवच का मूल मंत्र दसों दिशाओं से रक्षा करना है। सड़क पर चलते समय दसों दिशाओं से रक्षात्मक ड्राइविंग तभी संभव है जब हमारी आँखें और कान चारों तरफ सजग हों। गाड़ी चलाते समय पीछे देखने का शीशा रियर-व्यू मिरर साइड मिरर और सड़क पर लगे यातायात संकेत ही हमारी दसों दिशाओं के प्रहरी हैं। अपनी लेन में चलना और मोड़ों पर संकेत (इंडिकेटर) देना ही असल मायने में दिशाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, जो अदम्य ऊर्जा, अपार शक्ति और आक्रामकता का प्रतीक है। लेकिन माँ उस हिंसक सिंह पर अत्यंत शांत और पूर्ण नियंत्रण के साथ विराजमान रहती हैं। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में आज की गाड़ियों के आधुनिक इंजन भी उसी सिंह की तरह शक्तिशाली हैं। यदि चालक का उन पर नियंत्रण न हो, तो वे विनाश का कारण बनते हैं। सूनी सड़क या एक्सप्रेस-वे देखकर गाड़ी की रफ्तार को बेकाबू न होने देना, बल्कि निर्धारित गति सीमा के भीतर रखना ही सिंह पर नियंत्रण है। मिश्रा कहते है माँ नवदुर्गा के नौ स्वरूप और सड़क सुरक्षा के व्यावहारिक नियम माँ शैलपुत्री स्थिरता व धैर्य जैसे घर से समय पर निकलें ताकि सड़क पर जल्दबाजी या आपाधापी न करनी पड़े ।माँ ब्रह्मचारिणी ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती न लांघना और हमेशा नियमों का तप की तरह पालन करना। माँ चंद्रघंटा अनावश्यक हॉर्न न बजाकर ध्वनि प्रदूषण न फैलाना और एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता देना। माँ कुष्मांडा रोड रेज से बचना; सड़क पर किसी की गलती पर गुस्सा करने के बजाय संयम से काम लेना। माँ स्कंदमाता बच्चों को हमेशा कार की पिछली सीट पर बैठाना और दुपहिया पर उन्हें भी हेलमेट पहनाना। माँ कात्यायनी शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसी आत्मघाती आदत का समूल नाश करना। माँ कालरात्रि रात या कोहरे में हाई-बीम की जगह डिपर और फॉग लाइट्स का सही प्रयोग करना। माँ महागौरी वाहन की फिटनेस सही रखना, प्रदूषण नियंत्रित रखना और सड़क पर कचरा न फेंकना। माँ सिद्धिदात्री यातायात नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन कर सुरक्षित घर लौटना ही जीवन रक्षा की सबसे बड़ी सिद्धि है। नवरात्रि का जीवन रक्षा का महासंकल्प नवरात्रि में हम जो उपवास रखते हैं, वह हमारी इंद्रियों के संयम का प्रतीक है। यही संयम हमें सड़क पर भी दिखाना है। घर-घर में जलने वाली अखंड ज्योति हमें संदेश देती है कि हमारे जीवन की ज्योति भी अखंड रहनी चाहिए, जो मोबाइल पर बात करने या बिना हेलमेट गाड़ी चलाने जैसी एक छोटी सी लापरवाही से कुल दीपक बुझ सकता है।

जनहित में सड़क सुरक्षा : संकल्प।

आइए, इस वर्ष की नवरात्रि पूजा में माँ दुर्गा के चरणों में इन वचनों को अपने जीवन का संकल्प बनाएं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग भूलकर भी न करें। दुपहिया वाहन पर दोनों सवारियाँ हमेशा आईएसआई मार्क हेलमेट पहनें और कार में बैठते ही सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। तेज़ गति रोमांच नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम लाती है; हमेशा निर्धारित गति सीमा का पालन करें ।सड़क पर धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि जीवन अनमोल है और कोई आपका घर पर इंतज़ार कर रहा है। मैं यातायात के नियमों का पूर्ण निष्ठा से पालन करूँगा क्योंकि यह जीवन अनमोल है और माँ कभी नहीं चाहतीं कि उनका कोई भी भक्त असुरक्षित घर लौटे ।जल्दबाज़ी में ना खोएँ होश, सड़क सुरक्षा में ही है समझदारी का जोश।

शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन सजग: डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने बहादुरगढ़ में शहरी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक में दिए जरूरी निर्देश

जल निकासी, सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

वार्ड स्तर पर शहरी निकाय से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान दें अधिकारी, आपसी समन्वय से तैयार करें कार्य योजना



बहादुरगढ़, 14 अक्टूबर

डीसी वर्षा खांगवाल ने बुधवार को नगर परिषद सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए शहर की जल निकासी व्यवस्था, सड़कों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति और शहरी सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर के प्रत्येक वार्ड में शहरी निकाय से संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जल निकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर

डीसी ने कहा कि शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज सिस्टम की नियमित निगरानी और सफाई सुनिश्चित की जाए। जिन क्षेत्रों में जल निकासी को लेकर समस्याएं सामने आती हैं, उनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाएं। शहर की सड़क या गली में सीवरेज या गड्ढे खुले न हो, इसके लिए नप अधिकारी नियमित मोनिटरिंग करें। कोई व्यक्ति चोटिल न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सड़कों की सफाई और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था हो दुरुस्त

डीसी ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सड़कों और गलियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। वार्ड स्तर पर सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार किए जाएं। उन्होंने स्ट्रीट लाइट की स्थिति का भी जायजा लेने और खराब लाइटों को जल्द ठीक करवाने के निर्देश दिए, ताकि शहरवासियों को आवागमन में सुविधा मिले और रात्रि के समय सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

स्वच्छ पेयजल आपूर्ति नागरिकों की प्राथमिकता

डीसी वर्षा खांगवाल ने पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी करें। कहीं भी पाइपलाइन में लीकेज, पेयजल आपूर्ति में बाधा या अन्य समस्या सामने आने पर तुरंत समाधान किया जाए। साथ ही शहर की सफाई, सीवरेज व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार काम किया जाए।

वार्ड स्तर पर समस्याओं की पहचान कर करें समाधान

डीसी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक वार्ड में समस्याओं की पहचान कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारी नियमित निरीक्षण करें और कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करने से ही शहर की व्यवस्थाओं में प्रभावी सुधार लाया जा सकता है। डीसी ने शहर के वार्ड पार्षदों से भी बातचीत की और उनके सुझाव लिए।

कूड़ा करकट जलाने वालों पर हो कार्रवाई

डीसी वर्षा खांगवाल ने शहरी क्षेत्र में नगर परिषद अधिकारियों को कूड़ा करकट जलाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और प्रदूषित वातावरण करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई पंचायती जमीन पर कूड़ा कचरा जलाते हुए मिले तो सम्बन्धित की पहचान करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण किसी भी रूप से न हो इसके लिए अधिकारी गम्भीरता से कदम उठाए।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी, पूर्व वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा, राजपाल जांगड़ा, दिनेश शेखावत के अलावा जिला प्रशासन की ओर से एडीसी एवं डीएमसी जगनिवास, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिवाच, ईओ संजय रोहिल्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी योजनाओं से रूबरू हो रहे श्रद्धालु



बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्टाल पर आमजन को कानूनी जानकारी दे रही पीएलवी

बेरी(झज्जर), 14 अक्टूबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत 11 अक्टूबर से बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर परिसर में स्टॉल लगाकर प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शारदीय नवरात्र आश्विन मेला को लेकर प्राधिकरण द्वारा लगाई गई स्टाल पर पीएलवी आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्रदान कर रही हैं। इस स्टाल का कानूनी जानकारी के लिए लोग खूब लाभ उठा रहे हैं।

देवी दर्शन उपरांत श्रद्धालु इस स्टाल पर पहुँच कर पीपीपी, आधार कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य जानकारी ले रहे हैं। दूसरी ओर सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर के सचिव विशाल ने बताया बेरी मेला में आने वाले नागरिकों को निशुल्क कानूनी जानकारी देने के लिए पैरा लीगल वालंटियर सरोज देवी, नीता देवी व बबीता देवी की ड्यूटी लगाई गई है, जोकि मेले में माता के दर्शनार्थ आने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उसे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। उन्होंने मेला में आने वाले श्रद्धालुओं का आह्वान किया कि वे माता के दर्शन उपरांत विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्टाल पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए योजनाओं का लाभ उठाएं।

माता भीमेश्वरी देवी का मुख्य मेला कल से, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : डीसी





डीसी वर्षा खांगवाल ने बेरी मंदिर परिसर का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सीसीटीवी निगरानी के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश

16 से 19 अक्टूबर तक चलेगा मुख्य मेला, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से करेंगे कार्य

बेरी (झज्जर), 14 अक्टूबर।

धर्मनगरी बेरी स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर आयोजित मुख्य मेले आयोजन इस बार 16 से 19 अक्टूबर तक होगा। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। बुधवार को डीसी वर्षा खांगवाल ने मंदिर परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी वर्षा खांगवाल ने मंदिर में माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा पुजारी पंडित कुलदीप वशिष्ठ से मन्दिर से जुड़ी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने श्रद्धालुओं के दर्शन, भीड़ प्रबंधन और अन्य सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम एवं माता भीमेश्वरी देवी श्राइन बोर्ड की सीईओ रेणुका नांदल ने उन्हें मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन सतर्क

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ का सुचारू प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें, ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें। श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा-अर्चना के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि मेले में श्रद्धालुओं की अधिक आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए। प्रमुख स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल तैनात किया जाए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाएं। किसी भी अप्रिय घटना अथवा अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए संबंधित अधिकारी पूरी सतर्कता बरतें।

सीसीटीवी से होगी निगरानी, आपात स्थिति से निपटने के लिए रहें तैयार

डीसी ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकतानुसार नियंत्रण कक्ष के जरिए निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों को अग्निशमन यंत्रों, चिकित्सा सहायता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए संबंधित टीमें तैयार रहें और श्रद्धालुओं को समय पर सहायता उपलब्ध करवाई जाए।

प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील

डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन और मेला आयोजन से जुड़ी समितियों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तुरंत पुलिस अथवा संबंधित अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के माता के दर्शन कर सकें। मेला परिसर के दौरे के दौरान डीसी वर्षा खांगवाल ने मेले में लगी दुकानों का भी अवलोकन किया।

पीड़ितों को समय पर मिले राहत, जिम्मेदार एजेंसियों की तय होगी जवाबदेही : डीसी

पात्र नागरिकों को निर्धारित समय अवधि में मिले दयालु-द्वितीय योजना का लाभ - डीसी - डीसी वर्षा खांगवाल ने जिला स्तरीय बैठक में की दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत दयालु द्वितीय योजना की समीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज



झज्जर, 14 अक्टूबर। डीसी वर्षा खांगवाल ने लघु सचिवालय स्थित सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय बैठक में अधिकारियों के साथ दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत दयालु-द्वितीय योजना की विस्तार से समीक्षा की। इस बीच जिला सांख्यिकी अधिकारी युद्धवीर सिंह ने योजना की विस्तार से जानकारी साझा की और बताया कि योजना के अंतर्गत छह आवेदन प्राप्त हुए हैं।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि यह योजना हरियाणा के निवासियों के लिए है। इस योजना के तहत लावारिस-आवारा/जंगली पशुओं जैसे गाय, बैल, कुत्ते, नील गाय, भैंस आदि के काटने-चोट मारने से हुई आकस्मिक मृत्यु/ घायल होने/ दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत पंजीकृत सभी परिवारों को कवर करना है।

डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत दयालु-द्वितीय योजना शुरू की है। इसमें आवारा पशुओं/पशुओं के कारण हुई दुर्घटना/घटना के संबंध में किए गए दावे के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य पीड़ित को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या नॉर्म अनुसार प्रतिशत दिव्यांगता होने पर एक से पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक परिवार के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। एफआईआर की कॉपी की जरूरी है।

कठिन समय में पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दयालु योजना

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि यह योजना कठिन समय में पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए है। ऐसे में इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न की जाए। आवेदकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए सत्यापन व दस्तावेजी कार्रवाई समय पर पूरी की जाए। साथ ही अधिकारियों की जॉइंट टीम घटनास्थल का दौरा करते हुए रिपोर्ट तैयार करे, ताकि पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण के कोई भी आवेदन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए गहन जांच करना बेहद जरूरी है।

- इस प्रकार मिलता है पीड़ित लोगों को दयालु-द्वितीय योजना का लाभ

जिला सांख्यिकी अधिकारी युद्धवीर सिंह ने बताया कि 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए एक लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के लिए दो लाख रुपए, 18-25 वर्ष के लिए तीन लाख, 25 से 45 वर्ष आयु तक के लिए पांच लाख रुपए, 45 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए तीन लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी/दावेदार को दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर सहायता हेतु योजना के ऑनलाइन पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in के माध्यम से आवेदन करना जरूरी है। सभी आवश्यक दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, एफआईआर/डीडीआर, मृत्यु प्रमाण पत्र और अस्पताल डिस्चार्ज प्रमाणपत्र जरूरी है।

इन विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर सीटीएम ऋषु, डीडीपीओ निशा तंवर, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ राजेन्द्र मलिक, एडीटीओ राजेश मलिक, पीडब्ल्यूडी से एक्सईएन सुमित कुमार व अनिल रोहिल्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा सेतु कैंप से ग्रामीणों को मिल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी





साल्हावास में लगे सेवा सेतु कैंप से ग्रामीणों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में 17 अक्टूबर तक जारी है सेवा संकल्प अभियान

झज्जर, 14 अक्टूबर। सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत बुधवार को साल्हावास ब्लॉक में सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सतेंद्र जाखड़ ने कैंप का अवलोकन किया। बीडीपीओ राहुल मेहरा ने उनका स्वागत किया। कैंप में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, सेवाओं, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी।

डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैंप का उद्देश्य सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है। सतेंद्र जाखड़ ने ग्रामीणों से कैंप में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी लेने और पात्रता के अनुसार लाभ उठाने का आह्वान किया।

कैंप में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जहां नागरिकों को स्वास्थ्य जांच के साथ स्वस्थ जीवनशैली संबंधी परामर्श दिया गया। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

दिल्ली परिवहन विभाग — नियमों की खुली अवहेलना ?

भर्ती से पंजीकरण तक, कोर्ट आदेश से महिला सुरक्षा तक — जब जानकारी, पुख्ता सबूत और ऑनलाइन डाटा सबके पास है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं ?

— प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष

भूमिका: सवाल दिल्ली का, जवाब व्यवस्था का दिल्ली का परिवहन विभाग केवल गाड़ियों का पंजीकरण करने वाला दफ्तर नहीं है। यह दिल्ली की सांस, सड़क, सुरक्षा और व्यवस्था का नियामक है। जब इसी विभाग पर भर्ती नियमों की अवहेलना, प्रमोशन में मनमानी, न्यायालयों के आदेशों की अवमानना और पंजीकरण में फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह केवल विभागीय मामला नहीं रह जाता — यह संविधान, कानून और जनता के मूल अधिकारों का सवाल बन जाता है।

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, इन सभी बातों की जानकारी, पुख्ता सबूत और ऑनलाइन डाटा का पूरा विवरण परिवहन आयुक्त, विशेष परिवहन आयुक्त एवं विशेष आयुक्त विजिलेंस परिवहन को है। फिर भी व्यवस्था मौन है। यही मौन सबसे बड़ा सवाल है।

मुख्य तथ्य: 12 गंभीर मुद्दे — एक ही विभाग में

क्रम मुद्दा

1 भर्ती के नियमों की खुली अवहेलना

2 प्रमोशन में नियमों की खुली अवहेलना

3 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना

4 उपराज्यपाल दिल्ली के आदेशों की खुली अवहेलना

5 उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशों की खुली अवहेलना

6 CAT के आदेशों, दिशा निर्देशों की खुली अवहेलना

7 4 पहिया में पास वाहन का पंजीकरण 3 पहिया में

8 जिस श्रेणी के पंजीकरण पर रोक है, उसे बेखौफ पंजीकरण

9 आधार कार्ड में नाम कुछ और, पंजीकरण दूसरे नाम से

10 जनहित के नाम पर पॉलिसी/स्कीम, पालन के लिए वाहन मालिकों को धमकियां

11 गृह मंत्रालय की महिला सुरक्षा कमेटी के निर्देशों की अवहेलना — व्यावसायिक घराने का नुकसान बचाने के लिए

12 जनता से लूट और व्यावसायिक घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सब कुछ

मुख्य बिन्दु 1: भर्ती और प्रमोशन में नियमों की अवहेलना — संविधान का उल्लंघन

संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 16 — सरकारी नौकरी में समान अवसर
- अनुच्छेद 309-311 — भर्ती और सेवा शर्तें

जब भर्ती और प्रमोशन में नियमों की अवहेलना होती है, तो यह केवल दो कर्मचारियों का झगड़ा नहीं है। यह योग्य अभ्यर्थियों के मूल अधिकारों का हनन है। भर्ती नियम (Recruitment Rules) संसद/विधानसभा की अनुमति से बनते हैं। इनकी अवहेलना कानून की अवहेलना है।

परिणाम: विभाग में योग्यता की जगह मनमानी, कर्तव्यनिष्ठा की जगह चापलूसी, और अनुभव की जगह सांठगांठ हावी हो जाती है।

मुख्य बिन्दु 2: न्यायालयों और उपराज्यपाल के आदेशों की अवहेलना — अवमानना का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, CAT और उपराज्यपाल — ये चारों संवैधानिक संस्थाएं हैं। इनके आदेशों की अवहेलना का अर्थ है:

– सुप्रीम कोर्ट: अनुच्छेद 129 और 142 — अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई का अधिकार

- हाई कोर्ट: अनुच्छेद 215 — अवमानना की शक्ति
- CAT: प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिनियम 1985 — केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवा विवादों का निर्णय
- उपराज्यपाल: दिल्ली सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनके निर्देशों का उल्लंघन

जब एक ही विभाग एक साथ चार स्तरों के आदेशों को नजरअंदाज करता है, तो यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, सिस्टमैटिक अवमानना है।

मुख्य बिन्दु 3: पंजीकरण घोटाला — 4 पहिया पास, 3 पहिया में पंजीकृत यह सबसे गंभीर आरोप है।

कानून क्या कहता है: मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 39 — बिना पंजीकरण वाहन नहीं चलेगा। धारा 44-46 — पंजीकरण प्रक्रिया। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 — वाहन की श्रेणी, टाइप अप्रूवल।

आरोप:

- भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों (ARAI, ICAT आदि) द्वारा 4 पहिया में पास वाहन को 3 पहिया में पंजीकृत कर दिया जाता है।
- जिस श्रेणी के वाहन के पंजीकरण पर रोक है, उसका बेखौफ पंजीकरण कर दिया जाता है।
- आधार कार्ड में वाहन मालिक का नाम कुछ है, पंजीकरण दूसरे नाम से कर दिया जाता है।

इसका अर्थ:

1. सड़क सुरक्षा खतरे में — गलत श्रेणी का वाहन गलत परमिट, गलत बीमा, गलत टैक्स पर चलेगा।
2. राजस्व की हानि — गलत श्रेणी में कम टैक्स।
3. अपराध की संभावना — गलत नाम पर पंजीकृत वाहन अपराध में इस्तेमाल हो सकता है, असली मालिक को फंसाया जा सकता है।
4. बीमा क्लेम में धोखा — दुर्घटना के समय बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी।

यह केवल गलती नहीं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आता है।

मुख्य बिन्दु 4: जनहित के नाम पर पॉलिसी, धमकियों के नाम पर वसूली आरोप है कि एक तरफ जनहित के नाम पर पॉलिसी/स्कीम घोषित की जाती है, पर अमल कराने के लिए वाहन मालिकों को धमकियां दी जाती हैं।

संवैधानिक दृष्टिकोण:

- अनुच्छेद 19(1)(g) — व्यवसाय करने की स्वतंत्रता
- अनुच्छेद 21 — जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
- मोटर वाहन अधिनियम में जबरन वसूली का कोई प्रावधान नहीं

पॉलिसी का उद्देश्य सुविधा होना चाहिए, भय नहीं। यदि पॉलिसी अच्छी है, तो जनता उसे स्वीकार करेगी। धमकियां देना इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी जनहित की नहीं, किसी विशेष व्यावसायिक घराने के हित की है।

मुख्य बिन्दु 5: महिला सुरक्षा समिति के निर्देशों की अवहेलना गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए बनाई गई कमेटी के दिशा निर्देशों को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसमें उनके प्राय व्यावसायिक घराने का नुकसान हो सकता है।

गंभीरता:

- निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, वर्मा कमेटी की सिफारिशें, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 में सुरक्षा प्रावधान — सब अनिवार्य हैं।
- दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऑटो/टैक्सी में सुरक्षा, GPS, पैनिक बटन, CCTV, ड्राइवर वेरिफिकेशन — ये सब महिला सुरक्षा से जुड़े हैं।

जब महिला सुरक्षा के निर्देशों को व्यावसायिक लाभ के लिए ताक पर रख दिया जाता है, तो यह मानवाधिकार का उल्लंघन है, न कि केवल प्रशासनिक चूक।

मुख्य बिन्दु 6: जनता से लूट, घरानों को फायदा — नीति या साजिश ? आरोप नंबर 12 सबसे व्यापक है। जनता से लूट और व्यावसायिक घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ भी किया जाता है।

इसके रूप:

- फिटनेस, परमिट, पंजीकरण में अनावश्यक शुल्क
- दलालों की मिलीभगत
- बड़ी कंपनियों को मनमाफिक परमिट, छोटे ऑपरेटरों को परेशानी
- वाहनों की अवैध पार्किंग, अवैध कब्जा पर कार्रवाई में पक्षपात

यह लोक हित (Public Interest) के विपरीत निजी हित (Private Interest) का शासन है।

अब आप ही बताएं: ऐसे में कैसे संभव है ? यही इस लेख का मूल प्रश्न है, जो परिवहन विभाग के अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए:

- वायु गुणवत्ता संभव ? — जब गलत श्रेणी में पंजीकृत, बिना फिटनेस वाले, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे, तो प्रदूषण कैसे रुकेगा ?
- सड़कों से जाम खत्म होना संभव ? — जब अवैध वाहनों की संख्या बढ़ेगी, तो सड़कें जाम ही होंगी।
- दुर्घटना मुक्त दिल्ली संभव ? — जब गलत नाम, गलत श्रेणी, बिना वेरिफिकेशन के वाहन चलेंगे, तो दुर्घटना कैसे रुकेगी ?
- अवैध पार्किंग खत्म होना संभव ? — जब अवैध वाहनों का ही पंजीकरण हो रहा है, तो पार्किंग व्यवस्था कैसे बनेगी ?
- सड़कों और पटरियों पर अवैध कब्जा खाली होना संभव ? — जब विभाग ही अवैधता को वैधता दे रहा है, तो कब्जा कैसे हटेगा ?
- अवैध वाहनों का सड़कों पर दौड़ना बंद होना संभव ? — जब पंजीकरण ही अवैध तरीके से हो रहा है, तो अवैध वाहन वैध हो जाते हैं।

उत्तर सीधा है: जब तक विभाग में नियम, कानून और न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं होगा, तब तक दिल्ली में कोई भी सुधार संभव नहीं है।

निष्कर्ष: कार्रवाई की मांग — परिवहन विशेष की अपील

परिवहन विशेष की ओर से मांग है:

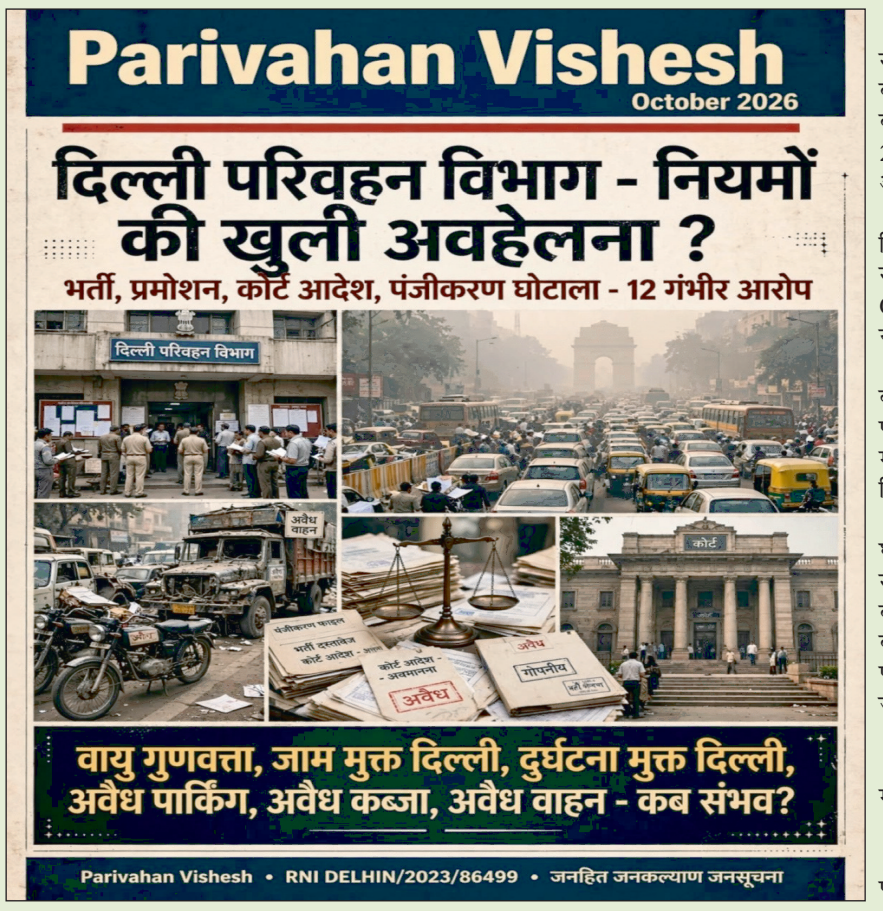
1. तत्काल जांच: दिल्ली के उपराज्यपाल, CBI, विजिलेंस और CAG द्वारा स्वतंत्र जांच
2. ऑनलाइन डाटा की फॉरेंसिक जांच: पंजीकरण डाटा, आधार लिंकिंग, टाइप अप्रूवल डाटा का मिलान
3. भर्ती/प्रमोशन की पुनः समीक्षा: CAT और हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार
4. महिला सुरक्षा निर्देशों का तत्काल पालन
5. अवैध पंजीकरण रद्द: गलत श्रेणी, गलत नाम वाले सभी पंजीकरणों की जांच और रद्दीकरण

जनहित, जनकल्याण और जनसूचना के लिए यह आवश्यक है कि जनता को सत्य पता चले। पत्रकारिता का धर्म यही है — सत्ता के सामने सवाल रखना, जनता के सामने सत्य रखना।

जय हिंद, जय संविधान, जय जनता।

— संजय कुमार बाठला, प्रधान संपादक। पिंकी कुंडू, सह संपादक परिवहन विशेष

RNI DELHIN/2023/86499



होम्योपैथिक कंपनी एडविन बायोटेक के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज करने का न्यायालय ने दिया आदेश



लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला,कंपनी के प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा सहित अन्य पर गंभीर आरोप

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तिवारी की प्रभावी पैरवी पर वाराणसी की अदालत ने थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का दिया निर्देश

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- होम्योपैथिक दवाओं के कारोबार से जुड़ी कंपनी एडविन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा सहित अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी, विश्वासघात एवं धन हड़पने के मामले में वाराणसी की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (वरिष्ठ श्रेणी), कोर्ट संख्या-04,वाराणसी ने प्रार्थिनी सुधा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए थाना लालपुर- पाण्डेयपुर पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। प्रार्थिनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तिवारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष वित्तीय लेनदेन,व्यापारिक अनुबंध संबंधी विवाद एवं कथित धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।

प्रार्थिनी सुधा सिंह के अनुसार एडविन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आदेश शर्मा तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों ने सुनियोजित तरीके से आकर्षक व्यापारिक लाभ एवं अधिकृत डीलरशिप का प्रलोभन देकर उनसे बड़ी धनराशि निवेश कराई। आरोप है कि कंपनी के जिम्मेदार व्यक्तियों ने व्यापारिक अनुबंध एवं निर्धारित लाभ देने का भरोसा दिलाया लेकिन बाद में अपने वादों से मुकर गए। प्रार्थिनी का आरोप है कि उन्होंने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लगभग 11 लाख रुपये का निवेश किया। इसके अतिरिक्त कंपनी से जुड़े धनश्याम सिंह ने सिक्योरिटी मनी के नाम पर दो अलग-अलग चेकों के माध्यम से कुल आठ लाख रुपये प्राप्त किए। इस धनराशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने तथा स्टाम्प पेपर पर लिखित अनुबंध उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन बार-बार मांगने के बावजूद न तो अनुबंध दिया गया और न ही धनराशि वापस की गई।

आरोप है कि कंपनी से जुड़े व्यक्तियों के आचरण एवं कथित अनियमितताओं के कारण प्रार्थिनी का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाजार में लाखों रुपये की बकाया धनराशि फंस गई तथा बड़ी मात्रा में दवाइयां स्टॉक में पड़ी रह गईं। प्रार्थिनी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर आर्थिक शोषण तथा धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थिनी ने इस संबंध में पूर्व में पुलिस अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की थी लेकिन अपेक्षित कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पुलिस आख्या का परीक्षण करने के उपरांत पाया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा कराया जाना आवश्यक है। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना भारतीय की अदालत ने 13 अक्टूबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष लालपुर- पाण्डेयपुर को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराने का आदेश दिया।

प्रार्थिनी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश तिवारी ने कहा कि न्यायालय का यह आदेश पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निष्पक्ष पुलिस विवेचना से पूरे प्रकरण की वास्तविकता सामने आएगी तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगी।।

22 दिनों का शांतिपूर्ण धरना — Gate D, सुप्रीम कोर्ट: लीगल फ्रेटर्निटी के लिए न्याय की पुकार

Justice for the Legal Fraternity — Together We Stand for a Stronger, Fairer and Brighter Legal Profession

— प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, परिवहन विशेष

भूमिका: 22 दिन — शांति, धैर्य और संकल्प की मिसाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के Gate D पर पिछले 22 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण धरना भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। यह कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं, बल्कि काले कोट की गरिमा, संविधान की मर्यादा और अहिंसक प्रतिरोध की परंपरा का प्रतीक है।

देश के विभिन्न राज्यों से आए लीगल colleagues ने इस धरने में शामिल होकर अपना समर्थन व्यक्त किया है। संदेश स्पष्ट है — न्याय की रक्षा के लिए वकील समुदाय एकजुट है।

मुख्य तथ्य: धरने का पूरा विवरण

स्थान: Gate D, Supreme Court of India, नई दिल्ली

अवधि: 22 Days of Peaceful Sit-In Protest

आह्वान तिथि: 15 अक्टूबर 2026 — Turn Out In Large Numbers

मुख्य नारे:

- Stronger Lawyers, Brighter Future
- United For Justice
- Gate D, Supreme Court of India

उद्देश्य: आने वाली पीढ़ी के लिए Legal Profession का उज्जवल भविष्य सुरक्षित करना — न्यायसंगत, निष्पक्ष और मजबूत कानूनी व्यवस्था की स्थापना।

मुख्य बिन्दु: क्यों यह धरना महत्वपूर्ण है ?

बिन्दु 1: शांतिपूर्ण प्रतिरोध — लोकतंत्र की ताकत 22 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठना आसान नहीं है। धूप, बारिश, भीड़, प्रशासनिक दबाव के बावजूद वकीलों ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। यही गांधीवादी सत्याग्रह की परंपरा है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है।

शांतिपूर्ण धरना संवैधानिक अधिकार है — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा का अधिकार देता है। जब वकील अपने ही अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण ढंग से बैठते हैं, तो यह संविधान की जीवंतता का प्रमाण है।

बिन्दु 2: Legal Fraternity की एकता — राज्यों से समर्थन इस धरने की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह किसी एक राज्य, एक बार एसोसिएशन या एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों से आए कानूनी सहयोगियों ने इसमें भाग लिया है।

यह एकता दर्शाती है कि समस्या स्थानीय नहीं, व्यवस्था से जुड़ी है। जब युवा वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता और कानून के छात्र एक साथ खड़े होते हैं, तो यह पूरे न्यायिक तंत्र के लिए चेतावनी और अवसर दोनों है।

बिन्दु 3: Next Generation के लिए लड़ाई धरने का आह्वान साफ कहता है:

> "To make this protest a success and help secure a bright future for the next generation entering the legal profession."

आज लॉ कॉलेजों से निकलने वाले हजारों युवा वकीलों के सामने चुनौतियां हैं — इंटर्नशिप, बार एनरोलमेंट, काम की कमी, आर्थिक असुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता। यदि आज वरिष्ठ पीढ़ी इन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाएगी, तो कल का न्याय तंत्र कमजोर होगा।

मजबूत वकील ही मजबूत न्याय व्यवस्था की नींव हैं।

बिन्दु 4: न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के बीच संवाद की जरूरत यह धरना न्यायपालिका के विरोध में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के साथ संवाद की मांग है। भारत में वकील और न्यायाधीश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वकीलों की चिंताओं को सुना जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान संवाद से निकलना चाहिए।

इतिहास गवाह है कि जब भी बार और बेंच के बीच संवाद टूटा है, न्याय व्यवस्था को नुकसान हुआ है। जब संवाद हुआ है, तो सुधार हुए हैं।

बिन्दु 5: जनता के लिए संदेश आम जनता को यह समझना होगा कि वकीलों का यह संघर्ष केवल वकीलों का नहीं है। यदि वकील समुदाय कमजोर होगा, तो आम आदमी को न्याय मिलने में और देरी होगी, न्याय महंगा होगा और न्याय से विश्वास उठेगा।

Stronger Lawyers = Stronger Justice for Common Man

निष्कर्ष: Together We Stand 22 दिनों का यह शांतिपूर्ण धरना यह साबित करता है कि कानूनी बिरादरी अपने अधिकारों और भविष्य के लिए एकजुट, अनुशासित और दृढ़ है।

परिवहन विशेष की ओर से हमारी अपील है कि सभी कानूनी सहयोगी इस शांतिपूर्ण संघर्ष को समर्थन दें, संविधान की मर्यादा में रहें और संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता खोलें।

Justice for the Legal Fraternity — Together We Stand for a Stronger, Fairer and Brighter Legal Profession.

जय हिंद, जय संविधान।



युवा शक्तिः शिक्षा, संस्कार और कौशल- सशक्त भविष्य के तीन स्तंभ



● डॉ. विजय गर्ग



किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी की सोच, योग्यता और मूल्यों पर निर्भर करता है। युवा केवल देश की आबादी का एक हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे देश की प्रगति, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के वास्तविक वाहक हैं। यदि युवाओं को सही शिक्षा, अच्छे संस्कार और आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएँ, तो वे न केवल अपना जीवन सफल बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की नींव तीन महत्त्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी होती है—शिक्षा, संस्कार और कौशल। ये तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं। केवल शिक्षा प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, यदि उसके साथ नैतिक मूल्य और व्यावहारिक कौशल न हों। इसी प्रकार, अच्छे संस्कारों और कौशलों को सही दिशा देने के लिए ज्ञान भी आवश्यक है।

शिक्षाः सोच को नई दिशा देने का माध्यम

शिक्षा मनुष्य को केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे तर्कशील बनाती है, प्रश्न पूछने का साहस देती है और सही-गलत में अंतर करने की समझ विकसित करती है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो ज्ञानवान होने के साथ-साथ जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और समाज के प्रति संवेदनशील भी हों।

आज तेजी से बदलते संसार में शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल साधनों और अनुसंधान के क्षेत्रों में नई संभावनाएँ पैदा हो रही हैं। इसलिए युवाओं को रटने के बजाय समझकर सीखने, तर्क करने, समस्याओं का समाधान खोजने और नई चीजों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियाँ प्राप्त करना या नौकरी हासिल करना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना भी है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना समझदारी और दृढ़ता के साथ कर सकें।

संस्कारः सफलता को सही दिशा देने वाली शक्ति

शिक्षा मनुष्य को ज्ञान देती है, लेकिन संस्कार उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते हैं। ईमानदारी, सम्मान, करुणा, अनुशासन, सहनशीलता, जिम्मेदारी और दूसरों की सहायता करने की भावना अच्छे संस्कारों के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सफलता की दौड़ कभी-कभी युवाओं को नैतिक मूल्यों से दूर कर सकती है। अंकों, डिग्रियों, वेतन और पदों को ही सफलता का मापदंड मान लेना उचित नहीं है। वास्तविक सफलता वह है, जिसमें व्यक्ति अपनी उन्नति के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों और कल्याण का भी ध्यान रखे।

परिवार, विद्यालय और समाज युवाओं में अच्छे संस्कार विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे केवल उपदेशों से ही नहीं, बल्कि बड़ों के व्यवहार और जीवनशैली से भी सीखते हैं। इसलिए माता-पिता और शिक्षकों को अपने आचरण के माध्यम से ईमानदारी, मेहनत, सहयोग और मानवता के मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

अच्छे संस्कारों वाला युवा अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता, बल्कि उसका उपयोग समाज की बेहतरी के लिए करने का प्रयास करता है।

कौशलः ज्ञान को व्यवहार में बदलने की क्षमता

आधुनिक संसार में केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है; उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता भी आवश्यक है। कौशल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने, अपना व्यवसाय शुरू करने, नई समस्याओं का समाधान खोजने और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम बनाते हैं।

संवाद-कला, कंप्यूटर का ज्ञान, डिजिटल साक्षरता, आलोचनात्मक चिंतन, टीम में काम करने की क्षमता, समय प्रबंधन और निर्णय लेने की योग्यता आज के महत्त्वपूर्ण कौशल हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवाओं और उद्यमिता से जुड़े कौशल भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई के साथ-साथ प्रयोगात्मक कार्य, परियोजनाएँ, इंटर्नशिप, खेलकूद और व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचियों और योग्यताओं को पहचानने का अवसर मिलेगा।

कौशलयुक्त युवा केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं बनते, बल्कि रोजगार पैदा करने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। इस प्रकार वे देश की आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

तीनों का समन्वय ही वास्तविक शक्ति

शिक्षा, संस्कार और कौशल को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। शिक्षा के बिना कौशलों का विकास सीमित रह सकता है, संस्कारों के बिना ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में हो सकता है और कौशलों के बिना ज्ञान व्यावहारिक जीवन में अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता।

एक डॉक्टर के पास चिकित्सा संबंधी ज्ञान और तकनीकी कौशल होने के साथ-साथ मरीजों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। एक शिक्षक को अपने विषय की जानकारी के साथ विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने की क्षमता भी चाहिए। इसी प्रकार, एक वैज्ञानिक, प्रशासक, इंजीनियर या उद्यमी के लिए ज्ञान और कौशल के साथ नैतिकता भी आवश्यक है।

जब ये तीनों गुण एक साथ विकसित होते हैं, तो युवा आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनते हैं।

माता-पिता, शिक्षकों और समाज की भूमिका

युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना केवल सरकार या शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। यह परिवार, शिक्षकों, समाज और स्वयं युवाओं की साझा जिम्मेदारी है।

माता-पिता को बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उनकी विशिष्ट योग्यताओं को पहचानना चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और नैतिक जिम्मेदारी विकसित करनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों को ऐसा वातावरण देना चाहिए, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।

सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं तक डिजिटल साधनों, पुस्तकालयों और उचित मार्गदर्शन की पहुँच सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है।

युवाओं को भी अपने समय का सदुपयोग करना, लगातार सीखते रहना, असफलताओं से सबक लेना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए।

निष्कर्ष

युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूँजी है। लेकिन इस शक्ति को सही दिशा देने के लिए शिक्षा, संस्कार और कौशलों का संतुलित विकास आवश्यक है। शिक्षा युवाओं को सोचने की क्षमता देती है, संस्कार उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और कौशल उन्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के योग्य बनाते हैं।

यदि हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकें, जो ज्ञानवान होने के साथ नैतिक, कुशल और समाज के प्रति जिम्मेदार भी हो, तो एक समृद्ध, समानतापूर्ण और विकसित भारत का सपना अवश्य साकार हो सकता है।

सशक्त युवा, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र—इसी में हमारे भविष्य की वास्तविक शक्ति निहित है।

डॉ. विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात शिक्षाविद् स्ट्रीट कौर

फुटबॉल की सुंदरता उसकी अनिश्चितता में भी है। कागज पर कोई टीम कितनी ही मजबूत क्यों न दिखाई दे, अंतिम परिणाम मैदान पर ही तय होता है। कुछ ही सेकंड में गोलकीपर नायक बन सकता है। कोई युवा स्थानापन्न खिलाड़ी पूरे मैच की दिशा बदल सकता है। एक सटीक पास गोल का कारण बन सकता है, जबकि एक छोटी-सी गलती इतिहास बदल सकती है।



IS INDIA NEXT ? - साउथ एशिया के पैटर्न से भारत को क्या सीखना चाहिए ?



श्रीलंका से बांग्लादेश तक एक जैसा पैटर्न – जब नैरेटिव ही हथियार बन जाए, तब क्रिटिकल थिंकिंग ही बचाव है

प्रस्तुतकर्ता संजय कुमार बाठला
प्रधान संपादक परिवहन विशेष

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि :

पिछले कुछ वर्षों में साउथ एशिया में एक चिंताजनक समानता देखी गई -

- श्रीलंका (2022): आर्थिक संकट, राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा
- बांग्लादेश (2024): राजनीतिक उथल-पुथल, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा
- पाकिस्तानः प्रधानमंत्री जेल में
- नेपालः यूथ सड़कों पर, संसद पर हमला
- म्यांमारः संस्थागत ढांचा ध्वस्त

ये सभी अलग देश, अलग सरकारें हैं, पर तर्क है कि हर जगह पहले युवाओं को सिस्टम के खिलाफ खड़ा करने का एक नैरेटिव बना।

मुख्य बिंदु - विश्लेषण:

1. एंटी-एस्टेब्लिशमेंट इकोसिस्टम कैसे बनता है? जैसे-जैसे कुछ क्रिएटर्स के फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उनके आसपास पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है - पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, मीम पेज, सेलेक्टिव जर्नलिस्ट, आउटरेज क्रिएटर्स। सब मिलकर एक ही नैरेटिव स्देश में कुछ नहीं बचा, सिस्टम खत्म, फ्यूचर खत्मस को एम्प्लिफाई करते हैं।

2. समस्या पर भावना, समाधान पर सन्नाटा? दूसरा बड़ा सवाल - क्या ये इकोसिस्टम समाधान भी देता है? लेखक का कहना है कि बेरोजगारी पर इमोशनल वीडियो तो मिलेंगे, पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर गंभीर चर्चा नहीं। शिक्षा पर आक्रोश मिलेगा, पर पॉलिसी रोडमैप नहीं। अंत में हर मुद्दे का निष्कर्ष सिर्फ स्सरकार हटाओस्र पर आकर रुक जाता है।

3. नैरेटिव वॉरफेयर - आधुनिक युद्ध का नया मोर्चा किसी भी स्थिर देश को बाहर से हराना मुश्किल है, इसलिए मॉडर्न वॉरफेयर अब बॉर्डर पर नहीं, नैरेटिव्स पर लड़ी जाती है। मीम्स हथियार बनते हैं, इन्फ्लुएंसर पॉलिटिकल एसेट्स बनते हैं, एल्गोरिदम साइकोलॉजिकल बैटलग्राउंड बन जाते हैं। मकसद - ट्रस्ट तोड़ो, समाज को बांटो, देश को भीतर से अस्थिर बनाओ।

संपादकीय निष्कर्ष - जनहित में क्या करें? यह कहना कि हर विरोध गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है। इतिहास यह भी बताता है कि कई बार जेनुइन पब्लिक एंगर को वैचारिक समूह, राजनीतिक अवसरवादी और बाहरी नैरेटिव हाईजैक कर लेते हैं।

इसलिए आज सबसे जरूरी स्किल है - क्रिटिकल थिंकिंग।

जनता के लिए 4 सवाल - किसी भी वायरल कैंपेन को शेयर करने से पहलेः

1. स्रोत क्या है? क्या यह सत्यापित है?
2. क्या यह सिर्फ भावनाएं भड़का रहा है या तथ्य और समाधान भी दे रहा है?
3. क्या इसका मकसद जागरूक करना है या सिर्फ संस्थाओं पर अविश्वास पैदा करना?
4. क्या डिस्ट्रैक्शन को ही क्रांति बताया जा रहा है?

इतिहास बार-बार बताता है कि जब युवाओं को यह विश्वास दिला दिया जाए कि संस्थाओं को तोड़ना ही स्वतंत्रता है, तब तक खेल खेला जा चुका होता है। इसलिए सोचो, समझो, जांचो, फिर भरोसा करो।

प्रमाण से आगे चित्रणः देखने, कल्पना करने और समझने की शक्ति

डॉ. विजय गर्ग

मानव समझ की शुरुआत हमेशा प्रमाण से नहीं होती। कभी-कभी इसकी शुरुआत किसी चित्र, उदाहरण, कहानी, आरेख या अनुभव से होती है, जो हमें वह देखने में सहायता करता है जिसे केवल शब्दों के माध्यम से समझाना कठिन होता है। चित्रण केवल किसी विचार को प्रस्तुत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अमूर्तविचारों और मानवीय मस्तिष्क के बीच एक सेतु है। यह जटिल अवधारणाओं को सरल बनाता है, कल्पनाशक्ति को प्रोत्साहित करता है और समझ के नए रास्ते खोलता है।

विज्ञान और गणित में प्रमाण का विशेष महत्त्व है। किसी गणितीय कथन को तार्किक तर्कों के माध्यम से सिद्ध करना आवश्यक होता है, जबकि वैज्ञानिक दावे के लिए साक्ष्य, अवलोकन और परीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर भी, प्रमाण को समझने से पहले विद्यार्थी को अक्सर किसी उदाहरण या चित्रण की आवश्यकता होती है। एक आरेख ज्यामितीय संबंधों को स्पष्ट कर सकता है, कोई मॉडल मशीन की कार्यप्रणाली समझा सकता है और एक प्रयोग किसी अपरिचित वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रत्यक्ष अनुभव में बदल सकता है।

गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ही लें। गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करने वाले गणितीय नियम सटीक हैं, लेकिन पेड़ से गिरता हुआ सेब इस घटना को समझने का एक सरल उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह उदाहरण गुरुत्वाकर्षण के संपूर्ण सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता, लेकिन जिज्ञासा और खोज की शुरुआत अवश्य करता है। इसी प्रकार, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन का चित्र विद्यार्थी को कोण की अवधारणा समझने में सहायता कर सकता है, जिसके बाद वह उसके गुणों के औपचारिक प्रमाण को आसानी से समझ सकता है।

शिक्षा में चित्रण का विशेष महत्त्व है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी सीखने और समझने का अलग तरीका अपनाता है। कुछ विद्यार्थी भाषा के माध्यम से, कुछ चित्रों और दृश्य प्रस्तुतियों से, जबकि अन्य व्यावहारिक गतिविधियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से बेहतर सीखते हैं। जो शिक्षक व्याख्या, चित्रण और तार्किक प्रमाण का समन्वय करता है, वह अधिक प्रभावशाली शिक्षण वातावरण तैयार करता है। इसका उद्देश्य तार्किक विवेचन का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसे अर्थपूर्ण और सुलभ बनाना है।

हालाँकि, चित्रण की एक सीमा भी है—*जो बात देखने में विश्वसनीय लगती है, वह आवश्यक नहीं कि सत्य भी हो।* कोई एक उदाहरण सार्वभौमिक गणितीय नियम को सिद्ध नहीं कर सकता। ग्राफ का पैमाना बदलकर भ्रामक निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आकर्षक चित्र किसी वैज्ञानिक दावे को गलत रूप में दिखा सकता है, जबकि भावनात्मक कहानी पर्याप्त प्रमाण के बिना हमारी सोच को प्रभावित कर सकती है। इसलिए चित्रण का उद्देश्य जाँच-पड़ताल के लिए प्रेरित करना होना चाहिए, न कि बिना प्रश्न किए किसी बात को स्वीकार करवाना।

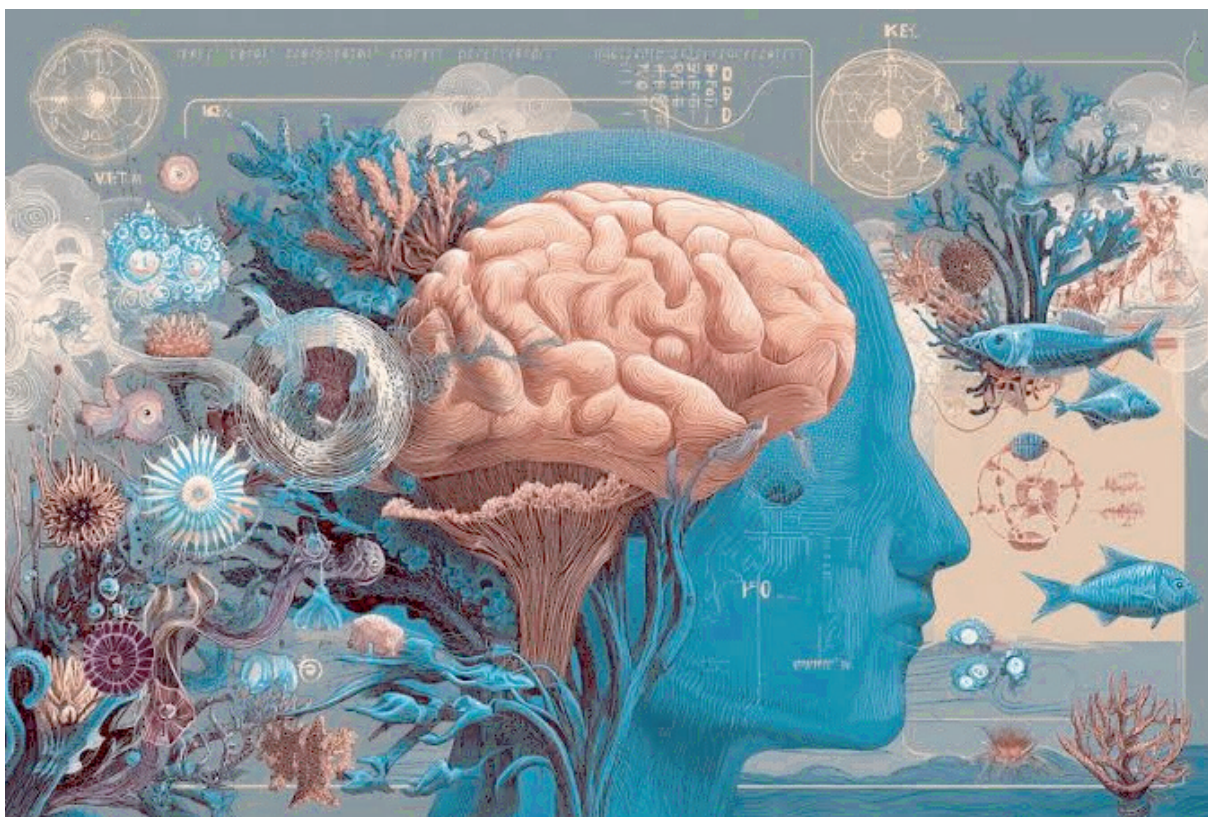
यह अंतर सार्वजनिक जीवन में भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक भाषणों, विज्ञापनों, सोशल मीडिया पोस्ट और समाचारों में लोगों की राय प्रभावित करने के लिए चित्रों, व्यक्तिगत कहानियों और चुनिंदा उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। ऐसे चित्रण महत्त्वपूर्ण मुद्दों को समझने योग्य बना सकते हैं, लेकिन संदर्भ से अलग प्रस्तुत किए जाने पर वास्तविकता को विकृत भी कर सकते हैं। एक जागरूक पाठक को यह पूछना चाहिए कि क्या दिया गया उदाहरण व्यापक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है और क्या उपलब्ध साक्ष्य निष्कर्ष को उचित ठहराते हैं।

गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ही लें। गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन करने वाले गणितीय नियम सटीक हैं, लेकिन पेड़ से गिरता हुआ सेब इस घटना को समझने का एक सरल उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह उदाहरण गुरुत्वाकर्षण के संपूर्ण सिद्धांत को सिद्ध नहीं करता, लेकिन जिज्ञासा और खोज की शुरुआत अवश्य करता है। इसी प्रकार, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन का चित्र विद्यार्थी को कोण की अवधारणा समझने में सहायता कर सकता है, जिसके बाद वह उसके गुणों के औपचारिक प्रमाण को आसानी से समझ सकता है।

वैज्ञानिक संचार में चित्रण उन खोजों को समझाने का प्रभावशाली साधन है, जिन्हें आम लोगों के लिए समझना कठिन हो सकता है। परमाणुओं के मॉडल, मानव मस्तिष्क के आरेख और जलवायु परिवर्तन के दृश्य चित्रण जटिल प्रणालियों को समझने में सहायता करते हैं। फिर भी, प्रत्येक मॉडल वास्तविकता के कुछ पहलुओं को सरल बनाता है। उसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह क्या सही ढंग से समझाता है और उसकी सीमाएँ क्या हैं।

इस प्रकार, चित्रण और प्रमाण का संबंध विरोध का नहीं, बल्कि पूरकता का है। चित्रण हमें कल्पना करने, अवलोकन करने और प्रश्न उठाने में सहायता करता है। प्रमाण हमें यह जाँचने में मदद करता है कि हमारे निष्कर्ष तार्किक और अनुभवजन्य आधार पर कितने उचित हैं। एक समझ विकसित करता है, जबकि दूसरा किसी दावे की विश्वसनीयता स्थापित करने में सहायता करता है। दोनों मिलकर रचनात्मकता और बौद्धिक अनुशासन को बढ़ावा देते हैं।

यह संबंध शिक्षकों, लेखकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण सीख प्रस्तुत करता है। केवल निष्कर्ष बताने के बजाय उन्हें यह समझाना चाहिए कि विचार कैसे विकसित होते हैं, सार्थक उदाहरण देने चाहिए और विद्यार्थियों को अपने सामने प्रस्तुत तथ्यों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल प्रभावशाली चित्रण की प्रशंसा करना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे मौजूद तर्क की जाँच करना भी सीखना चाहिए।



दैनिक जीवन में हम करुणा के किसी कार्य से दयालुता, कठिन निर्णय से साहस और किसी व्यक्ति के आचरण से ईमानदारी को समझते हैं। ऐसे उदाहरण मानवीय मूल्यों को वास्तविक रूप प्रदान करते हैं। फिर भी, विवेक की माँग है कि हम किसी एक घटना के आधार पर अंतिम निर्णय न लें, बल्कि व्यवहार के व्यापक स्वरूप को भी समझें।

अंततः, प्रमाण से आगे चित्रण का अर्थ सत्य से दूर जाना नहीं है। इसका अर्थ यह समझना है कि कठोर तार्किक विवेचन को समझने से पहले मनुष्य को अक्सर कल्पना, अनुभव और उदाहरणों की आवश्यकता होती है। चित्रण समझ का द्वार खोलता है, जबकि साक्ष्य और प्रमाण यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि हमारी समझ कितनी विश्वसनीय है।

एक अच्छा चित्रण किसी विचार को स्पष्ट करता है, जबकि ठोस प्रमाण उसकी वैधता स्थापित करता है। शिक्षा तब वास्तव में प्रभावशाली बनती है, जब वह हमें दोनों का उपयोग करना सिखाती है—स्वतंत्र रूप से कल्पना करना, निर्भीक होकर प्रश्न पूछना और सावधानीपूर्वक तर्क करना। प्रभावशाली चित्रों और अधूरी जानकारियों से भरी दुनिया में किसी उपयोगी उदाहरण और विश्वसनीय प्रमाण के बीच अंतर कर पाना केवल शैक्षणिक कौशल नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नागरिकता और आजीवन सीखने का एक आवश्यक आधार है।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। प्रख्यात गणितज्ञ
स्ट्रीट कौर चंद, एमएचआर,

भारतीय मानक ब्यूरो के नोएडा एवं गाजियाबाद शाखा कार्यालयों द्वारा विश्व मानक दिवस 2026 का संयुक्त आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा, 14 अक्टूबर 2026। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नोएडा एवं गाजियाबाद शाखा कार्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से 14 अक्टूबर 2026 को होटल गौर्स सरोवर प्रीमियर, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा में विश्व मानक दिवस 2026 मनाया गया। इस वर्ष का विषय "Shared Vision for a Better World" के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य-7 (SDG 7) — "Affordable and Clean Energy" (सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा) पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योगों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के बीच भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, गुणवत्ता-आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करना तथा सस्ती, विश्वसनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना था।

मुख्य अतिथि का संबोधन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री भाल चंद्र त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी (CDO), गौतम बुद्ध नगर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने सतत विकास और जनकल्याण के लिए गुणवत्ता एवं मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा ऊर्जा संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उप महानिदेशक, BIS का संबोधन

भारतीय मानक ब्यूरो की उप महानिदेशक (DDG) श्रीमती स्नेहलता ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय गुणवत्ता अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा भारतीय मानकों को व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मानकीकरण उत्पादों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।



गाजियाबाद शाखा कार्यालय प्रमुख का संबोधन

गाजियाबाद शाखा कार्यालय की प्रमुख श्रीमती जी. भवानी ने भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उद्योगों और उपभोक्ताओं के बीच गुणवत्ता संस्कृति को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने MSMEs एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों को लागू भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादन प्रक्रियाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मानकों का अनुपालन उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायक है।

नोएडा शाखा कार्यालय प्रमुख का संबोधन

नोएडा शाखा कार्यालय के प्रमुख श्री कौशिक दत्ता ने अपने संबोधन में भारतीय उद्योगों, विशेषकर MSMEs, के बीच मानकीकरण के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मानकों को अपनाने से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, बाजार में विश्वसनीयता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने SDG 7 के संदर्भ में ऊर्जा दक्षता, सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करने में मानकों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने उद्योगों, मानक क्लबों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों से गुणवत्ता जागरूकता के प्रसार में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

दीप प्रज्ज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। विभिन्न विद्यालयों के BIS मानक क्लबों से आए विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ एवं विषय-आधारित नाटक प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से गुणवत्ता, मानकीकरण, उपभोक्ता जागरूकता, ऊर्जा संरक्षण तथा सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया।

भारतीय उद्योगों एवं MSMEs में मानकीकरण को बढ़ावा

कार्यक्रम में भारतीय उद्योगों एवं MSMEs को भारतीय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्योग प्रतिनिधियों एवं रिसोर्स पर्सन्स ने गुणवत्ता आश्वासन, औद्योगिक मानकों, मानकीकरण तथा ऊर्जा दक्षता से संबंधित विषयों पर अपने विचार एवं तकनीकी जानकारी साझा की। सत्रों में मानकों के अनुपालन, उत्पादों की विश्वसनीयता, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

BIS CARE App के प्रति जागरूकता

प्रतिभागियों को BIS CARE App की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें ऐप के माध्यम से ISI मार्क एवं अन्य लागू BIS प्रमाणन चिह्नों की प्रामाणिकता की जाँच करने तथा उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

उद्योग प्रतिनिधियों, रिसोर्स पर्सन्स, मानक क्लबों एवं NGOs का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों, रिसोर्स पर्सन्स, BIS मानक क्लबों के प्रतिनिधियों तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधियों को गुणवत्ता जागरूकता, मानकीकरण के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदान और सहभागिता के लिए सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह ने उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया।

गुणवत्ता संस्कृति एवं सतत विकास का संदेश

कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने कहा कि भारतीय मानकों को अपनाना केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सशक्त, सुरक्षित और सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी हितधारकों से गुणवत्ता संस्कृति को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

श्री दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम राज्य का राज्यपाल बनाएं जाने पर प्रो मनोज कुमार कैन ने दी बधाई और शुभकामनाएं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को 6 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई।दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम राज्य का राज्यपाल बनाया गया है।दुष्यंत कुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।भाजपा में विभिन्न दायित्वों का निर्वाहन कर चुके हैं।29 दिसंबर 1957 को दिल्ली के मलका गंज में जन्मे दुष्यंत जी आरंभ से ही दलित शोषित वंचितों की आवाज बनकर सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं।उन्होंने पूर्व में भाजपा के अनेक दायित्वों पर कार्य किया है :-राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महामंत्री;चुनाव प्रभारी उत्तराखंड,पंजाब अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष;दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष;पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व निगम पार्षद भी रहें हैं।इन्होंने बूथ स्तर से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी।आप विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में पदाधिकारी रह कर अपनी सेवाएं प्रदान करतें रहें हैं।



प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि आज हम दिल्ली वालों के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है क्योंकि आज दिल्ली से संबद्ध अनुसूचित जाति वर्ग के एक ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जिन्होंने एक सामान्य परिवार से अपना जीवन आरंभ किया।वह भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्य करते रहे।यह सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को विभिन्न दायित्व पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया।आज भाजपा ने दुष्यंत जी को सिक्किम राज्य का राज्यपाल नियुक्त करके अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान बढ़ाया।

51 लाख श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले कर्मयोगियों को नगर निगम ने किया सम्मानित

सोना लौटाने वाले दो सफाईकर्मियों को 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि, 90 से अधिक संगठनों और समाजसेवियों को मिला सम्मान

परिवहन विशेष न्यूज

गयाजी। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम-2026 के सफल आयोजन के बाद गया नगर निगम की ओर से बुधवार को हरिदास सेमिनरी के सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे सफाईकर्मियों, नगर निगम कर्मियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, पुलिसकर्मियों, चिकित्सकों, रेलकर्मियों, मीडियाकर्मियों, पंडा समाज और समाजसेवियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया।



कार्यक्रम की अध्यक्षता मेयर डॉ. वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने की, जबकि मंच संचालन पूर्व उपमहापौर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने किया। दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपमहापौर चिंता देवी, नगर आयुक्त डॉ. गगन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार सहित पार्षदगण और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले सफाईकर्मियों को विशेष सम्मान

तीर्थयात्री का खोया सोना लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले सफाईकर्मी जितेंद्र मांझी और राजेश कुमार को 5100-5100 रुपये की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। मेयर ने कहा कि कर्मचारियों की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण ही बड़े आयोजनों की सफलता का आधार है। उनके कार्य दूसरे कर्मचारियों को भी कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देंगे।

सामूहिक प्रयास से सफल हुआ महासंगम

मेयर ने कहा कि सफाई योद्धाओं, जिला प्रशासन, पुलिस, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज के सभी वर्गों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में सभी का योगदान सराहनीय रहा।

मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि मेले से पहले सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, पेयजल आपूर्ति और रोशनी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि यह समारोह सेवा, समर्पण और सामूहिक सहभागिता का सम्मान है।

ब्रेकिंग न्यूज़: सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी

Embassy of India
Riyadh
***
ADVISORY

In view of the current situation, all Indian nationals in the Kingdom of Saudi Arabia are advised to remain alert and vigilant, stay indoors as necessary, and follow the instructions issued by local authorities through official channels.

2. Indian nationals are strongly advised to refrain from circulating or reposting any videos or news related to the ongoing events.

3. The Embassy of India, Riyadh and the Consulate in Jeddah and its outsourced services through VFS, are continuing to function normally and will issue updates and advisories as and when necessary.

4. The 24x7 helpline of Pravasi Bharatiya Sahayata Kendra (PBSK) remains available on Toll free No: 8002471234.

5. The Indian community may follow the official social media handles of the Embassy for updates:

- X: @IndianEmbRiyadh
- Facebook: IndiainSaudiArabia
- Instagram: indianembriyadh
- LinkedIn: Embassy of India in Riyadh

Date: 08 October 2026
Place: Riyadh

रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है: "वर्तमान स्थिति को देखते हुए, सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहें और आधिकारिक माध्यमों से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारतीय नागरिकों को मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित किसी भी वीडियो या समाचार को प्रसारित करने अथवा दोबारा साझा करने से सख्ती से बचने की सलाह दी जाती है।"

बनभौरी मेले की सुरक्षा को लेकर हिसार पुलिस अलर्ट मोड पर, सीआईए बरवाला सहित 70 पुलिसकर्मी तैनात; भीड़ के मद्देनजर रोजाना भेजी जा रही अतिरिक्त कंपनी



नवरात्रों के मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, स्वैट कमांडो और डॉग स्क्वॉड की टीम भी तैनात : एसपी सिद्धान्त जैन

हरियाणा हिसार// राजेश सलूजा

नवरात्रों के अवसर पर थाना बरवाला क्षेत्र के गांव बनभौरी में आयोजित नौ दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिसार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस के निर्देशानुसार मेले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ को नियंत्रित करने तथा किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।

मेले की सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीआईए बरवाला टीम सहित 70 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन एक अतिरिक्त पुलिस कंपनी भी भेजी जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त स्वैट कमांडो टीम और डॉग स्क्वॉड की टीम लगातार मेले में निगरानी एवं जांच कर रही हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके और असामाजिक तत्वों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का मौका न मिले।

एसपी हिसार के निर्देश: मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने तथा भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

हिसार पुलिस की श्रद्धालुओं से अपील: मेले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। भीड़ के दौरान धैर्य बनाए रखें, अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें तथा कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत तैनात पुलिसकर्मियों को सूचित करें। हिसार पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षित और व्यवस्थित धार्मिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गया रेलवे स्टेशन पर 14.835 किलो चांदी के आभूषण बरामद, एक व्यक्ति हिरासत में



ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ की कार्रवाई, बरामद चांदी की अनुमानित कीमत 36 .34 लाख रुपये

गयाजी। पूर्व मध्य रेल के डीडीयू मंडल अंतर्गत गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन सतर्क के तहत कार्रवाई करते हुए 14.835 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं चांदी बरामद की है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दी गई है। बरामद चांदी की अनुमानित कीमत 36,34,575 रुपये बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को आरपीएफ गया के निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव के निर्देशन में आरपीएफ के अधिकारी एवं जवान गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली छोर स्थित फुट ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति पीठ पर बैग लेकर प्लेटफॉर्म संख्या छह और सात की ओर जाता दिखाई दिया। संदेह होने पर उसे रोककर पूछताछ की गई।

पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम जमशेद अली मलिक (36 वर्ष), निवासी ग्राम उदयचक, थाना दासपुर, जिला पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल बताया। उसके बैग की जांच करने पर उसमें 14.835 किलोग्राम चांदी के आभूषण एवं चांदी मिली। संबंधित चांदी के स्वामित्व एवं परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज वह मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए चांदी को जब्त कर व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। मामले की सूचना आयकर विभाग, पटना को दी गई। आयकर विभाग की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में आरपीएफ गया के उपनिरीक्षक इंद्र कुमार, प्रधान आरक्षक सचिंद्र कुमार, आरक्षक अमित कुमार, शशि शेखर एवं मुकेश कुमार के साथ सहायक उपनिरीक्षक अनिल कुमार चौधरी तथा सीपीडीएस गया के उपनिरीक्षक मुकेश कुमार शामिल थे।

सिंहभूम मे 16 पूजा के दरम्यान सुनैना के तीन नये शावक हुए सार्वजनिक

टाटा जू में तीन नये मेहमान , पिता रूद्र नागपुर से रहा है

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सिंहभूम , सिंहभूम मां सिंहवाहिनी का रहा है ।जहां की माता पाउड़ी देवी स्वयं बाघाम्बरी स्वरूपा हैं, आप अपना इसी ध्यान मंत्र में पूजित होती है ।.... और 16 दिनों का दुर्गात्सव उन्हीं के नाम आम जनता समूचे सिंहभूम में मनाते आये है अतीत राजबाड़ा काल खंड से ।इन्हीं दिनों जू ने शावकों को सार्वजनिक किया है ।

इन्हीं दिनों टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क (टाटा जू) में बाघों के कुनबे में तीन नए सदस्यों का आगमन हुआ है। यहां 23 सितंबर की सुबह बाघिन सुनैना ने दो मादा और एक नर शावक को जन्म दिया है।

चिड़ियाघर प्रबंधन ने शुरुआती दिनों में शावकों की देखभाल और स्वास्थ्य की निगरानी के बाद बुधवार को इसकी जानकारी सार्वजनिक की। तीनों शावकों के नामकरण के लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं। इच्छुक लोग 19 अक्टूबर तक अपने सुझाव भेज सकते हैं ।चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार, तीनों शावकों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। पहली बार मां बनी सुनैना ने अनजाने में एक मादा शावक को घायल कर दिया था। इसके बाद टाटा जू की पशु चिकित्सा टीम ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए शाविका के त्वचा पर आए घावों की सिलाई की ।उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। फिलहाल उसका वजन करीब 1.8 किलोग्राम है। उसे तत्काल खतरे से बाहर बताया गया है, हालांकि एहतियात के तौर पर चिकित्सक उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं।



वहीं, अन्य दोनों शावकों की स्थिति सामान्य है। नर शावक का वजन करीब 2.9 किलोग्राम और दूसरी मादा शावक का वजन लगभग 2.53 किलोग्राम है। तीनों शावकों की गतिविधियों पर पशु चिकित्सकों के साथ चिड़ियाघर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है

टाटा जू प्रबंधन के अनुसार, शावकों के पिता रुद्र को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर से लाया गया था ।चिड़ियाघर प्रबंधन ने बताया कि शावकों के जन्म की जानकारी पशु चिकित्सा प्रोटोकाल के तहत शुरुआती निगरानी और देखभाल की अवधि पूरी होने के बाद साझा की गई है।

टाटा जू प्रबंधन ने शहरवासियों को नामकरण प्रक्रिया से जोड़ने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की है। इसके तहत लोगों को तीनों शावकों के लिए एक-एक नाम सुझाना होगा।

नाम व्हाट्सएप या संदेश के माध्यम से 9438291637 पर भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

चिड़ियाघर की ओर से गठित समिति प्राप्त प्रविष्टियों में से तीन सर्वश्रेष्ठ सुझावों का चयन करेगी। चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित करने के साथ निःशुल्क चिड़ियाघर प्रवेश पास और स्मृति चिह्न प्रदान किया जाएगा।

प्रबंधन को उम्मीद है कि इस पहल से शहरवासी वन्यजीव संरक्षण से जुड़ेंगे और टाटा जू के नए मेहमानों के नामकरण में उत्साहपूर्वक भागीदारी करेंगे।



गढवा -कोलकाता बस के कंडक्टर को बेरहमी से पुलिस ने पीटा ,मामला तूल पकड़ा

एएसआई ने दी सफाई ,नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मामला , जांच का जिम्मा एसडीपीओ डूमरी को

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड



राची, दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर एक यात्री बस कंडक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है. घटना जिले के निमियाघाट थाना इलाके की है. कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप निमियाघाट थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार पर लगा है. आरोप है कि गढ़वा-कोलकाता चलने वाली मुन्ना ट्रेवल्स बस को रोककर उसके कंडक्टर संग एएसआई ने मारपीट की. घटना में कंडक्टर को चोट लगी है.

इधर, इस मामले की जानकारी पर गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने जांच शुरू कर दी है. जांच का जिम्मा डुमरी एसडीपीओ आबिद खान को दी गई है. एसडीपीओ आबिद ने जांच भी कर ली है. बताया जा रहा है कि बुधवार को जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एसपी आगे की कार्रवाई करे.

दरअसल, गढ़वा से कोलकाता के बीच मुन्ना ट्रेवल्स नामक बस चलती है. इसी बस से निमियाघाट में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र कुमार का परिवार 11 अक्टूबर को गढ़वा से निमियाघाट आ रहा था. बस पर सवार होने के दरमियान किसी बात को लेकर एजेंट से कहासुनी हुई.

इसके बाद 11-12 अक्टूबर की रात 12 बजे के बाद बस निमियाघाट पहुंची लेकिन अपने निर्धारित स्थान पर नहीं रूकी. जिसके बाद एएसआई बस के पीछे गए और आगे बस को रोका गया. यहां एएसआई का परिवार बस से उतरा और इसी दौरान कंडक्टर से विवाद हुआ. इसी दौरान बस कंडक्टर के सिर पर चोट लगी. ऐसे में इस मामले को लेकर बस के मालिक द्वारा पुलिस से शिकायत की गई. शिकायत के बाद एसपी ने एसडीपीओ को जांच का जिम्मा सौंपा.

कंडक्टर के साथ मारपीट के आरोप पर सहायक अवर निरीक्षक सतेंद्र कुमार से उनका पक्ष लिया गया. सतेंद्र ने कहा कि 11 अक्टूबर को उनकी पत्नी परिवार संग मुन्ना बस पर सवार हुई थी. 1600 रुपया का टिकट कटवाया. इस दौरान सीट को लेकर उसके परिवार के लोगों ने एजेंट से निवेदन किया तो एजेंट और कंडक्टर ने काफी भला-बुरा कहा.

उन्होंने भी फोन पर एजेंट और कंडक्टर से बात की. इसके बावजूद उनकी पत्नी संग दुर्व्यवहार किया गया. फिर सीट की जगह बेंच पर बैठाकर लाया गया. बाद रात में जब बस पहुंची तो बस को निमियाघाट के पास नहीं रोका गया बल्कि बस को आगे ले जाया गया.

उन्होंने बताया कि जब मैं पीछे से पहुंचा तो बस के कंडक्टर से वाहन को आगे ले जाने और पत्नी संग दुर्व्यवहार करने पर सवाल पूछा. मामला आत्मसम्मान से जुड़ा था तो इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मैंने कंडक्टर का गिरेबान पकड़ा. इसी दौरान कंडक्टर का सिर बस के दरवाजे से टकरा गया और उसे मामूली चोट लगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने मारपीट नहीं की है. सिर्फ पत्नी की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाया है.

दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोपी एएसआई पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है. बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस से भी कई सवाल पूछे हैं.

उन्होंने कहा बस के एजेंट ने टिकट का पैसा एएसआई के परिवार से लिया, इसी बात से नाराज होकर एएसआई द्वारा जीटी रोड पर बस का पीछा कर उसे रुकवाया गया और टिकट के पैसे को लेकर बस के कंडक्टर जाहिद आलम के साथ मारपीट की.उन्होंने कहा कि घटना के बाद उन्हें धमकियां भी दी गईं. गंभीर रूप से घायल जाहिद आलम अस्पताल में भर्ती हैं. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्हें देखने अस्पताल जा रहे उनके भाई की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई.

बाबूलाल ने सीएम को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस की इस गुंडागर्दी के कारण एक परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है. क्या पुलिस वालों के परिजनों से बस का भाड़ा लेना अपराध है ? आप तो अल्पसंख्यक समाज के बड़े हितैषी बनने का दावा करते हैं, लेकिन क्या सत्ता के संरक्षण में वसूली और मुफ्तखोरी के आगे आपके सारे दावे खोखले नहीं हो जाते ? बाबूलाल ने पुलिस एसोसिएशन को भी नसीहत दी है.

इधर, डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि एसपी के निर्देश पर आरोपी एएसआई से शो-कॉज किया गया है. वहीं आगे की जांच भी की गई है. जांच हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट पुलिस कप्तान को भेजी जा रही है. आगे वरीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई होगी

बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में 65.42 प्रतिशत मतदान के बीच समर्थकों में झड़प, मतगणना आज

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव में 65.42 प्रतिशत मतदान के बीच भाजपा और सपा समर्थित कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसपर पुलिस ने लाठी पटककर दोनों पक्षों को खदेड़ कर स्थिति सामान्य की। इसकी मतगणना आज 15 अक्टूबर को होगी। इसके लिए भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक चले मतदान में कुल 9,474 मतदाताओं में से 6,198 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार मतदान प्रतिशत में 6.63 प्रतिशत की गिरावट भी आई। जबकि पिछले चुनाव में 72 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार के मतदान में पुरुष मतदाताओं ने महिलाओं के मुकाबले अधिक सक्रियता दिखाई। साथ ही मतदान के अंतिम समय मेंबिना पहचान पत्र के वोट डालने को लेकर बेसिक प्राइमरी पाठशाला बिठूर, ध्रुव नगर-लक्ष्मीबाई नगर में बिना पहचान पत्र के वोट डालने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और सपा समर्थित कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी झड़प में बदल गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठी पटककर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए पांच मतदान केंद्रों पर 10 बूथ बनाए गए थे। सुबह से ही मतदाताओं का पहुंचना शुरू हो गया था। दिन चढ़ने के साथ मतदान की गति बढ़ी, लेकिन शाम पांच बजे मतदान समाप्त होने तक पिछले चुनाव का आंकड़ा नहीं छू सका। वहीं उपचुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सतर्क रहें। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि मतगणना के साथ ही परिणाम आज 15 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। याद रहे कि बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की लगातार पांच बार रहीं मां नगर पंचायत अध्यक्ष डा. निर्मला सिंह के 22 जून 2026 को निधन के फल स्वरूप ही उपचुनाव के लिए मतदान कराया गया है। भाजपा ने उनके बेटे राना समरेन्द्र सिंह को टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है।

बीजद की जनसंपर्क पदयात्रा में नवीन पटनायक का डबल इंजन सरकार पर हमला, बोले— 'किसान, महिलाएं, मध्यम वर्ग और गरीब, सभी परेशान'

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा



भुवनेश्वर: भुवनेश्वर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजू जनता दल (बीजद) की जनसंपर्क पदयात्रा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक शामिल हुए और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

नवीन पटनायक ने कहा कि बीजद सरकार के कार्यकाल में विकास मुख्य एजेंडा था, लेकिन डबल इंजन सरकार के लिए अपनी पार्टी का विकास ही मुख्य एजेंडा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किसान, महिलाएं, गरीब, मध्यम वर्ग और बुजुर्ग समेत सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि Gen Z यानी युवा पीढ़ी का भविष्य भी अंधकारमय होता जा रहा है।

नवीन ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर सरकार की नाकामियों को उजागर करने का आह्वान किया। नवीन पटनायक के आरोपों पर भाजपा के प्रदेश महासचिव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजद सरकार के समय ओडिशा किसानों की समस्याओं, खनन घोटालों, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और शिशु मृत्यु दर जैसे मामलों में देश में शीर्ष स्थान पर था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न घटनाओं की जांच को दबाने और भटकाने के मामले में भी ओडिशा आगे था। भाजपा नेता ने कहा कि बीजद सरकार के कार्यकाल में ओडिशा की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की नंबर एक पार्टी होने के कारण आज ओडिशा में पूर्ण बहुमत के साथ जनता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में नवीन पटनायक को आत्ममंथन करना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बीजद को जनता ने क्यों नकार दिया। भाजपा महासचिव ने कहा कि आत्ममंथन करने के बजाय नवीन पटनायक इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो उचित नहीं है।

ओडिशा के राज्यपाल बनाये जाने पर ब्रजमोहन राम ने 400 वर्ष पुरानी मंदिर मे मां उग्रतारा की पूजा की





ओडिशा के लोगों का जीवन बेहतर हो उनका रहेगा प्रयास

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

राची , जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन राम ओडिशा का राज्यपाल मनोनीत होने के बाद बुधवार को अपने पूरे परिवार के साथ गृह प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध मां उग्रतारा नगर भगवती मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र के महीने में माता रानी की कृपा से उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है. माता का आभार जताने वह यहां आए हैं.

दरअसल, बज्रमोहन राम चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी मोहल्ला के रहने वाले हैं. वह एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तीन बार पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसी बीच राष्ट्रपति ने उन्हें ओडिशा राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर दिया.

बज्रमोहन राम चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित कंचन नगरी मोहल्ला के रहने वाले हैं. वह एक बार लातेहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तीन बार पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्य कर चुके हैं. इसी बीच राष्ट्रपति ने उन्हें ओडिशा राज्य का राज्यपाल मनोनीत कर दिया. राज्यपाल के रूप में मनोनीत होने के बाद वह अपने गृह प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध नगर भगवती मंदिर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की और क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा. मौके पर उन्होंने कहा कि नवरात्र के महीने में केंद्र सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे माता की कृपा मानकर पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे

ब्रजमोहन राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें जिस उम्मीद और विश्वास के साथ नई जिम्मेदारी सौंपी है, उसपर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा. उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य का विकास है उनका लक्ष्य होगा.उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य में विकास की तमाम संभावनाएं हैं, परंतु कहीं ना कहीं यह राज्य अभी भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है. उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके इसके लिए पूरा प्रयास होगा.

छात्र संघ चुनाव से पहले उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में तनाव, दो छात्र गुटों के बीच झड़प

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा



भुवनेश्वर: छात्र संघ चुनाव से ठीक पहले उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कैंपस में आयोजित 'Why I Stand For' बैठक देखते ही देखते रणक्षेत्र में बदल गई और दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कल होने वाले छात्र संघ चुनाव से पहले विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 'Why I Stand For' बैठक में गैर-छात्रों की मौजूदगी को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों प्रतिद्वंद्वी गुट आमने-सामने आ गए।

इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और कई कुर्सियां तोड़ दी गईं। झड़प के कारण निर्धारित समय पर बैठक भी आयोजित नहीं हो सकी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। भुवनेश्वर के डीसीपी भी विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। उन्होंने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर आक्रोशित छात्रों को समझाने और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023